https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

पं. दीनदयाल उपाध्याय
पुण्यतिथि पर विशेष

वर्ष-14, अंक-04 16-28 फरवरी, 2019 (पाक्षिक) ₹20

5,00,000
रुपये तक की आय को आयकर से छूट

12 करोड़
छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता

पहली बार रक्षा बजट
3,00,000
करोड़ रुपये से अधिक

न्यू इंडिया का बजट

अनुसूचित जाति के लिए आवंटन में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि (76,801 करोड़ रुपये) और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत की वृद्धि (50,086 करोड़)

गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें

रेलवे के लिए समग्र पूंजी व्यय 1,58,658 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 19,000 करोड़ रुपये और मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये

मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली के कनेक्शन

बजट से गरीब को शक्ति, किसान को मजबूती और आर्थिक विकास को बल मिलेगा : प्रधानमंत्री

यह बजट वित्तीय समझदारी और जन-कल्याण के बीच एक अच्छा संतुलन है : अमित शाह

नई दिल्ली में 'भारत के मन की बात–मोदी के साथ' अभियान का शुभारंभ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह

देहरादून (उत्तराखंड) में एक विशाल त्रिशक्ति सम्मेलन को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कानपुर (उत्तर प्रदेश) में कानपुर–बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का स्वागत करते भाजपा उत्तर प्रदेश के नेतागण

पलास (आंध्र प्रदेश) में प्रजा चैतन्य यात्रा का शुभारंभ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

ओडिशा में 'भारत के मन की बात–मोदी के साथ' अभियान का शुभारंभ करते केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बसंत पांडा और अन्य

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 12 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता

अंतरिम बजट 2019-20 एक फरवरी को संसद में पेश किया गया। बजट में किसानों के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं तथा आयकर में बड़ी राहत की घोषणा की गयी। भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने औसत मुद्रास्फीति...

वैचारिकी

सही शब्द : सही अर्थ-2: प्रकृति, धर्म और संस्कृति 30

श्रद्धांजलि

पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस नहीं रहे 32

लेख

अंतरिम बजट (2019) और पांच साल की दिशा 22

अन्य

'देश के समग्र विकास एवं हर वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित बजट है' 17

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न 33

14 अंतरिम बजट 2019-20 की मुख्य बातें

केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए एक फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट की...

26 ओडिशा में जनजातियों की स्थिति बद से भी बदतर

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 फरवरी को भगवान् महाप्रभु की नगरी पुरी (ओडिशा) में विशाल...

27 'राज्य की भ्रष्टाचारी एवं अराजक तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकें'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 29 जनवरी को पूर्वी मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) जिले के कांथि रेलवे...

29 'उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने अमन कायम किया है'

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 फरवरी को अलीगढ़ में बूथ कार्यकर्ता...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

देश ने एनडीए की मजबूत सरकार देखी और देश ने उनकी मजबूर एवं मिलावटी सरकार देखी। अब ये लोग महामिलावटी सरकार की बात कर रहे हैं। भारत जैसे देश में महामिलावटी सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी।

@AmitShah

देश की सुरक्षा और हमारे जवानों का सम्मान मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। अमेरिका और इजराइल के बाद आज हिंदुस्तान तीसरा ऐसा देश है जो हमला करने वाले दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है।

@PiyushGoyal

पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी और विकास के लिये विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण जारी है, इससे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड तक की यात्रा आसान होगी। साथ ही, यह पुल पूर्वोत्तर में विकास और समृद्धि के नये द्वार खोलेगा।

facebook

प्रदेश के हर नागरिक के सुरक्षा की गारंटी ये सरकार देगी, लेकिन ओछे आरोप और अपने समय के कृत्यों पर इन लोगों को स्वयं विचार करना चाहिए। कैसे प्रदेश में दंगाइयों को बिठाकर मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते थे। हमारी सरकार आई तो वह पस्त है। आज दंगाई कह रहे हैं कि मुझे बख्श दो, हम ठेला लगा लेंगे। गुंडई भूल गए हैं। ठेला लगाकर अपने श्रम से स्वावलंबन की तरफ बढ़ो। सरकार कई योजनाएं ला रही हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना देश के अंदर एक अभिनव प्रयोग है।

— योगी आदित्यनाथ

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन का निर्माण तेजी से चल रहा है, जबकि चारधाम सम्पर्क के फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य प्रगति पर है। इस रेल लाइन से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की राह प्रशस्त होगी। नमामि गंगे के तहत STP निर्माण व सीवेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण अगस्त 2019 तक पूर्ण हो जाएगा।

— त्रिवेंद्र सिंह रावत

स्रोत - सोशल मीडिया

स्वातंत्र्यवीर सावरकर
पुण्यतिथि (26 फरवरी)
शत-शत नमन!

यह हर भारतीय का बजट है

यह अविश्वसनीय लग सकता है, परन्तु अब यह एक सच्चाई है– पिछले लगभग पांच वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपने झंडे बुलंदी से गाड़ दिये हैं। यह हर उस व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय है जिन्होंने कांग्रेस नीत यूपीए के भ्रष्टाचार, कुशासन, पॉलिसी पैरालिसिस, घोटाले एवं लूट का भयावह दौर देखा है। इस दौर में अर्थव्यवस्था के हर मानदंड पर देश न केवल बुरी तरह से पिछड़ गया था, बल्कि हर व्यक्ति के मन में नकारात्मकता एवं निराशा का भाव भर गया था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति अत्यधिक कमजोर पड़ गई थी। आर्थिक विकास की दर नीचे लुढ़क रही थी तथा देश मुद्रास्फीति एवं महंगाई का दंश झेल रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि हर कुछ नियंत्रण से बाहर हो और 'पॉलिसी पैरालिसिस' से ग्रस्त यूपीए सरकार कोई भी सुधारात्मक कदम नहीं उठा पा रही थी। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी और सरकार में बैठे लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था की समस्या पर दोष मढ़ हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में आज जब आर्थिक स्थिति न केवल सुदृढ़ हुई, बल्कि इतने कम समय में इसे वैश्विक पटल पर एक चमकते आर्थिक सितारे के रूप में देखा जाने लगा है। यह परिवर्तन अविश्वसनीय लगता है।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में जब अंतरिम बजट प्रस्तुत किया तब केन्द्र की मोदी सरकार के परिवर्तनकारी क्षमताओं पर जन–जन का विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया। मोदी सरकार के दौर में हर बजट के साथ जिस प्रकार व्यापक परिवर्तन की गाथा लिखी गई है उससे देश का आत्मविश्वास कई गुणा बढ़ चुका है। आज भारत न केवल विश्व का सबसे तेज गति का विकास दर वाला देश बन चुका है, बल्कि केवल पांच वर्षों में ग्यारहवें से छठे स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गई है और जल्द ही पांचवां स्थान पर आना सुनिश्चित कर लिया है। हर वर्ग की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के साथ–साथ वित्तीय अनुशासन एवं बजट घाटा को नियंत्रण रखने के लिये भी इस बजट की प्रशंसा हो रही है। यह पहली बार मोदी सरकार में ही हुआ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गरीब, मजदूर एवं किसान बजट के केन्द्र में आये और इन क्षेत्रों में भारी राशि का आवंटन हुआ। इसी क्रम में इस बार दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान को पीएम किसान योजना के तहत छह हजार रुपयों का प्रति किसान वार्षिक आवंटन कर एक भारी परिवर्तन की शुरुआत की गई है। इससे गरीब, सीमांत एवं अन्य किसानों को मजबूत किया गया है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इससे देश के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। आयकर में पांच लाख रुपये तक की छूट देकर मध्यम वर्गीय एवं नौकरीपेशा वर्ग को भारी राहत पहुंचाई गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये बजट में भारी बढ़ोतरी कर इन वर्गों के त्वरित विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। वास्तव में यदि देखा जाय तो इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है– यह हर भारतीय का बजट है, यह भारत का बजट है।

आयकर में पांच लाख रुपये तक की छूट देकर मध्यम वर्गीय एवं नौकरीपेशा वर्ग को भारी राहत पहुंचाई गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये बजट में भारी बढ़ोतरी कर इन वर्गों के त्वरित विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। वास्तव में यदि देखा जाय तो इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है– यह हर भारतीय का बजट है, यह भारत का बजट है।

पिछले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक लंबी यात्रा तय की है। कांग्रेस नीत यूपीए काल का लड़खड़ाता आर्थिक परिदृश्य अब पूरी तरह बदल चुका है और भारत को विश्व में एक उभरती हुई मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व का ही परिणाम है कि अर्थव्यवस्था न केवल पटरी पर वापस आई है, बल्कि यह विश्व में सर्वाधिक तेज विकास दर वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। नोटबंदी, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, भ्रष्टाचार विरोधी कानून, जीएसटी जैसे बड़े सुधारात्मक कदमों से अर्थव्यवस्था एवं पूरी व्यवस्था में एक नया प्राण फूंका गया है। यह केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जबरदस्त राजनैतिक इच्छाशक्ति एवं पक्के इरादे का ही परिणाम है कि देश आने वाले दिनों में सुनहरे भविष्य का इंतजार कर रहा है। आज भारत की आर्थिक संभावनाओं एवं शक्ति को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है और सभी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा कर रही हैं। आज जबकि गरीब एवं वंचित वर्गों का सशक्तिकरण हो रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के परिणामकारी नेतृत्व में देश समृद्धि एवं वैभव की ओर बढ़ चला है। एक नवीन भारत के उदय को पूरा विश्व देख रहा है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

12 करोड़ छोटे को प्रत्यक्ष

5 लाख वार्षिक

अंतरिम बजट 2019-20 एक फरवरी को संसद में पेश किया गया। बजट में किसानों के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं तथा आयकर में बड़ी राहत की घोषणा की गयी। भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने औसत मुद्रास्फीति को 4.6 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनाए रखा, जो किसी भी पिछली सरकार की मुद्रास्फीति दर से कम है। यह बजट देश को प्रगतिशील मार्ग पर आगे बढ़ाने हेतु एक माध्यम के रूप में याद किया जाएगा।

अंतरिम बजट 2019-20 में प्रत्यक्ष आय सहायता के साथ 12 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी योजना, असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों के

टे व सीमांत किसानों
ष आय सहायता

आमदनी तक कोई आयकर नहीं

लिए पेंशन योजना, 5 लाख वार्षिक तक की आमदनी के लिए आयकर में छूट, स्टैम्प ड्यूटी में सुधार, रक्षा के लिए अब तक का सबसे अधिक 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 58,166 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन, हरियाणा के लिए एक नया एम्स, विदेशी फिल्म निर्माताओं के समान भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी एकल खिड़की सुविधा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों समेत कमजोर वर्गों एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, ढांचागत सुविधाओं के लिए बजट आवंटन में बढ़ोत्तरी, 1.5 करोड़ मछुआरों के लिए मत्स्य पालन को एक पृथक विभाग बनाना प्रमुख हैं।

केंद्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एक फरवरी को संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया। इस बजट में किसानों के लिए एक बड़ी योजना तथा आयकर प्रदाताओं के लिए बड़ी राहत की बात कही गई। इसके अलावा इसमें आने वाले वर्षों के लिए विकास एजेंडा का भी उल्लेख है।

किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरुआत

छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि की जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बजट में 75 हजार करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2019-20 के लिए) तथा 20 हजार करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2018-19 का संशोधित अनुमान) के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना में 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 2,000 रुपये प्रत्येक तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम को दिसंबर, 2018 से प्रभावी माना जाएगा और इस अवधि की पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च, 2019 तक कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपये का आवंटन

इस वर्ष में ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन 750 करोड़ रुपये किया गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है। इससे गाय संसाधनों का सतत अनुवांशिक उन्नयन करने और गायों

'न्यू इंडिया का बजट देश में नई ऊर्जा का संचार करेगा'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए इसे न्यू इंडिया का बजट बताया और कहा कि इससे देश को नई ऊर्जा मिलेगी। 2019-20 का अंतरिम बजट संसद में पेश किये जाने के बाद इस पर कई ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे 12 करोड़ से ज्यादा किसान और उनके परिवार, तीन करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्गीय करदाता, पेशेवर और उनके परिवार तथा 30 से 40 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। 'न्यू इंडिया के इस बजट का धन्यवाद'।

श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार की ओर से विकास के लिए की गई पहल ने कइयों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है जो बजट में किसानों और मध्यम वर्ग के कल्याण, आयकर में राहत से लेकर बुनियादी ढांचे, विनिर्माण से लेकर एमएसएमई क्षेत्र, आवास से लेकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तथा न्यू इंडिया के निर्माण की तेज गति में परिलक्षित है।

उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों के गरीबी की जंजीरों से मुक्त होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारा नव मध्यमवर्ग लगातार बढ़ रहा है और उसके साथ ही उसके सपने भी बड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आयरकर में मिली राहत के लिए मध्यमवर्ग को बधाई देते हुए कहा कि वह देश के विकास के लिए किए गए उनके योगदान को सलाम करते हैं।

बजट में किसानों के हितों के लिए की गई पहलों के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई सालों से किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं का फायदा उन तक नहीं पहुंच पाया जो बेहद अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि किसानों के कल्याण के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है जिससे पांच एकड़ से कम भूमि रखने वाले छोटे किसानों को काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया के इस बजट में पशु पालन और मत्स्य पालन क्षेत्र का खास ध्यान रखा गया है।

असंगठित क्षेत्र के हितों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना काफी मददगार साबित होगी। इस क्षेत्र को अपने हितों की रक्षा की काफी दरकार थी जिसे न्यू इंडिया के बजट ने पूरा किया है। आयुष्मान भारत योजना और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी आम लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगी।

प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि समाज के हर वर्ग को विकास का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा यह बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा और अर्थव्यवस्था को नया बल देगा।

यह बजट लोगों की भलाई और कुशल वित्तीय प्रबंधन के बीच उचित समन्वय है। बजट में किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जबकि वित्तीय घाटे को मात्र 3.4 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है जो यूपीए के शासनकाल में 6 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। मोदी सरकार की विकासपरक नीतियों के कारण करदाताओं की संख्या 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 पहुंच गई। इसके कारण कर संग्रह 3.68 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसने कल्याणकारी योजनाएं बढ़ाने में सरकार की मदद की और अर्थव्यवस्था को नुकसान भी नहीं पहुंचा। –अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आयोग गायों के लिए कानूनों और कल्याण योजना को प्रभावी रूप से लागू का काम भी देखेगा।

मत्स्य पालन विभाग का सृजन

मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के बारे में सतत ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार ने अलग से मत्स्य पालन विभाग का सृजन करने का निर्णय लिया है। इस प्रयास के माध्यम से सरकार इस क्षेत्र पर निर्भर लगभग 1.45 करोड़ लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करना चाहती है।

वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियां कर रहे किसानों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ किया जाएगा। इसके अलावा ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाएगी।

असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को पेंशन

असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को पेंशन संबंधी लाभ उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन नामक नई योजना की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों के अंदर यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बन जाएगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। श्री गोयल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की जाएगी। इस योजना को चालू वर्ष से ही लागू किया जाएगा।

5 लाख वार्षिक आमदनी तक कोई आयकर नहीं

5 लाख रुपये तक की सालाना कर योग्य आमदनी वाले व्यक्तिगत करदाताओं को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्हें भी किसी प्रकार के आयकर के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि वे भविष्य निधि, विशेष बचतों, बीमा आदि में निवेश कर लेते हैं।

साथ ही 2 लाख रुपये तक के आवास ऋण के ब्याज, शिक्षा ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान, चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्त कटौतियों के साथ उच्च आय वाले व्यक्तियों को भी कोई कर नहीं देना होगा। इससे स्व-नियोजित, लघु व्यवसाय, लघु व्यापारियों, वेतनभोगियों, पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों सहित मध्यम वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती की राशि को मौजूदा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जा रही है। इससे 3 करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 4,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।

अपने कब्जे वाले किसी दूसरे घर पर सांकेतिक किराए पर आयकर पर छूट का अब प्रस्ताव किया गया है। फिलहाल ऐसे सांकेतिक किराए पर आयकर का भुगतान करना होता है, यदि किसी के पास अपने कब्जे में एक से अधिक घर हो।

बैंक/डाकघर बचतों पर अर्जित ब्याज के स्रोत पर कर कटौती को बढ़ाकर 10,000 रुपये से 40,000 रुपये किया जा रहा है। छोटे करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से किराए पर कर कटौती के लिए टीडीएस को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार घर खरीदने वाले पर जीएसटी के बोझ को कम करना चाहती है और इसी के अनुसार इस विषय पर जल्द से जल्द विचार करने और सुझाव देने के लिए जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के एक समूह को नियुक्त करने की पहल की थी। श्री गोयल ने कहा कि जल्द ही 90 प्रतिशत से अधिक जीएसटी, भुगतान करने वाले कारोबारियों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की अनुमति होगी।

5 वर्षों में औसत महंगाई दर 4.6 प्रतिशत

पिछले 5 वर्षों में सरकार औसत महंगाई दर को 4.6 प्रतिशत तक नीचे लाने में सफल रही है, जो किसी अन्य सरकार के कार्यकाल के दौरान महंगाई दर की तुलना में कम है।

'ऐतिहासिक अंतरिम बजट'

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अंतरिम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह न सिर्फ विकासोन्मुख है बल्कि इसमें मध्यमवर्ग, किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

बेहतरीन बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल को बधाई देते हुए श्री सिंह ने कहा कि पांच लाख तक की आय वाले लोगों को आयकर में छूट तथा डेढ़ लाख तक के निवेश में अतिरिक्त छूट से कर छूट की सीमा साढे छह लाख तक हो जाने से मध्यम वर्ग और खासतौर से नौकरीपेशा लोगों के जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के जरिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आय की ऐसी मदद प्रदान करेगी जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत दो एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे जो सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

किसानों के लिए बजट में किए गए राहत प्रावधानों का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पहले की सरकार ने किसानें को केवल अस्थायी राहत देते थी लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किसानों को स्थायी रूप से आर्थिक मदद पहुंचाएगी। इसके लिए बजट में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह काम आगे भी जारी रखेगी।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए सरकार अब किसानों को 60 साल की उम्र पूरू होने पर 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित करेगी। इसके लिए उन्हें मासिक रूप से महज 100 रुपये का प्रीमियम देना होगा।

गृहमंत्री ने कहा कि एक तरफ यह बजट जहां देश के सामाजिक ढांचे को बल देगा वहीं दूसरी और आर्थिक ढाचे को भी मजबूती प्रदान करेगा। बजट में रक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है।

न्यू इंडिया के निर्माण में यह बजट काफी मददगार बनेगा। इस बजट में 2030 तक भारत को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना को साकार करने के मुख्य बातों को शामिल किया गया है।

वस्तुतः दिसम्बर 2018 में महंगाई दर 2.19 प्रतिशत तक नीचे आ गई थी। श्री गोयल ने कहा कि यदि हमने महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया होता तो हमारे परिवारों को खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता वस्तुओं, आवास आदि जैसी मूलभूत जरूरतों पर 35-40 प्रतिशत अधिक खर्च करना पड़ता। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009-2014 के दौरान 5 वर्षों में औसत महंगाई दर 10.1 प्रतिशत के स्तर पर थी।

राजकोषीय घाटे में कमी

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे को 3.4 प्रतिशत तक नीचे लाया गया, जो 7 वर्ष पहले लगभग 6 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि चालू खाता घाटा इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के केवल 2.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि 6 वर्ष पहले यह 5.6 प्रतिशत था। श्री गोयल ने कहा, ''हमने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया, जबकि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश वित्त आयोग ने की थी, जिसे हमने सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के साथ स्वीकार किया और उसके परिणामस्वरूप राज्यों को अधिक धन दिया गया।"

उच्च वृद्धि दर

वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान अगली पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ढांचागत सुधारों की एक श्रृंखला में शामिल वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) की प्रस्तुति और अन्य कर सुधारों के बाद आने वाले दशकों में उच्च वृद्धि के मानक तय कर दिये गये हैं।

उन्होंने कहा कि देश पिछले पांच वर्षों के दौरान अपनी सर्वश्रेष्ठ वृहद आर्थिक स्थिरता के दौर का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि 1991 से प्रारंभ हुए आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार के द्वारा हासिल की गई आर्थिक वृद्धि के मामले में पिछले पांच वर्षों में उच्चतम वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के साथ हम दुनिया में एक तेजी के साथ उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट संबोधन में कहा कि वर्ष 2013-14 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थ्यवस्था से अब हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।

श्री गोयल ने कहा कि स्थिर और अनुमान योग्य नियामक शासन, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था एवं मजबूत बुनियादी आधारों के कारण भारत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में 239 बिलियन डॉलर की व्यापक धनराशि को आकर्षित करने में सक्षम रहा है।

प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटनों में वृद्धि

मनरेगा हेतु 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन

2019-20 के बजट अनुमानों के लिए

मनरेगा हेतु 60,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त आवंटन किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के 15,500 करोड़ रुपये की तुलना में 2019-20 के बजट अनुमानों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-18 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया।

मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली के कनेक्शन

मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली के कनेक्शन भी प्रदान किये जायेंगे। अब तक एक मिशन मोड के तहत 143 करोड़ एलईडी बल्ब प्रदान किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप गरीब और मध्यम वर्ग को 50,000 करोड़ की बचत हुई है।

देश में करीब 50 करोड़ लोगों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत' के अंतर्गत करीब 10 लाख रोगी निःशुल्क चिकित्सा के माध्यम से लाभांवित हो चुके हैं और इस चिकित्सा उपचार की लागत करीब 3,000 करोड़ रुपये होगी। लाखों गरीबों और मध्यम वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से किफायती मूल्यों पर आवश्यक दवा, हृदय के स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण के खर्च में कमी के साथ-साथ औषधियों की आसान उपलब्धता से भी लाभांवित हुए हैं।

वित्त मंत्री श्री गोयल ने बताया कि वर्ष 2014 में 21 एम्स संस्थानों की घोषणा के बाद से देश में 14 एम्स संस्थान या तो संचालित हैं अथवा स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में एक नये- 22वें एम्स संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की। समेकित बाल विकास योजना के लिए आवंटन को 2018-19 के संशोधित अनुमान के 23,357 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2019-20 के बजटीय अनुमान में 27,584 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 76,801 करोड़ रुपये का आवंटन

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 2018-19 के बजट अनुमान में 56,619 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, बाद में संशोधित अनुमान में इसे बढ़ाकर 62,474 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में इसे बढ़ाकर 76,801 करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना में 35.6 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए भी वर्ष 2019-20 के बजटीय अनुमान में यह धनराशि 39,135 करोड़ रुपये थी, जो 28 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पहुंच से वंचित गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लाभ के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत विशेष रणनीतियां तैयार करने के लिए एक कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के तहत एक समिति भी गठित की जाएगी, जो गैर-अधिसूचित, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों की पहचान के कार्य को पूरा करेगी।

उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए गए

उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य था। इसमें 6 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं और बकाया मुफ्त कनेक्शन भी अगले वर्ष तक दे दिये जायेंगे। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में जल्दी ही विकसित किया जाएगा। औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग को अब उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का नया नाम दिया जाएगा।

श्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश हित में ली गई नीतियों की दिशा में है। राजग सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बेड़ियों से मुक्त किया, इसकी क्षमता का विस्तार हुआ और विकास में यह हमें वैश्विक अग्रणी बनाया। हमारा लक्ष्य भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाना है। अगले दशक के मध्य में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और अगला मुकाम अर्थव्यवस्था के उस आकार को दुगुना करना है।

— अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार

देश का रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ से अधिक

वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि देश

का रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ से अधिक है। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान घरेलू विमान यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। संचालित हवाई अड्डों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। सिक्किम में पेकयोंग हवाई अड्डा शुरू हो गया है। अरूणाचल प्रदेश अभी हाल में हवाई यातायात मानचित्र पर आया है और मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम पहली बार देश के रेल मानचित्र पर आए हैं।

भारतीय रेल के लिए बजट में 64,587 करोड़ रुपये (2019-2020 बजट अनुमान) के पूंजीगत सहयोग का प्रस्ताव किया गया है। रेल का कुल पूंजीगत परिव्यय कार्यक्रम 1,58,685 करोड़ रुपये का है। वित्त और रेल मंत्री ने घोषणा की कि परिचालन अनुपात 2017-18 के 98.4 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 96.2 प्रतिशत और 2019-20 (बजट अनुमान) में 95 प्रतिशत होने का अनुमान जताया गया है।

पिछले पांच वर्षों में भारत की स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 10 गुनी बढ़ी

पिछले पांच वर्षों में भारत की स्थापित सौर

केंद्र सरकार का व्यय

2019-20 के लिए बजट अनुमान
(₹ करोड़ में)

पेंशन	1,74,300	ब्याज	6,65,061
रक्षा	3,05,296	आईटी और दूरसंचार	21,549
प्रमुख सब्सिडी	2,96,684	योजना एवं सांख्यिकी	5,594
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,49,981	ग्रामीण विकास	1,38,962
वाणिज्य और उद्योग	27,660	वैज्ञानिक विभाग	26,237
पूर्वोत्तर का विकास	3,000	सामाजिक कल्याण	49,337
शिक्षा	93,848	कर प्रशासन	1,17,285
ऊर्जा	44,101	राज्यों को अंतरण	1,66,883
विदेश मामले	16,062	परिवहन	1,56,187
वित्त	19,812	संघ राज्य क्षेत्र	15,042
स्वास्थ्य	63,538	शहरी विकास	48,032
गृह	1,03,927	अन्य	75,822
		कुल जोड़	27,84,200

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक सर्वहितकारी और लोकप्रिय बजट प्रस्तुत किया है, जो समाज के सभी वर्गों व राष्ट्र की रीढ़ जैसे- किसानों, मध्य वर्ग, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लाभकारी है। पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने निरंतर सुशासन प्रदान किया है। इसने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा और सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों खासकर- गरीबों, किसानों और मध्य वर्ग को प्राप्त हो। इस बजट में 5 लाख सालाना की आय वाला मध्य वर्ग पूरी तरह से आयकर मुक्त है। साथ ही, अनेक करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उनके भी लाखों रुपये कर दायरे से बाहर हैं।

—पीयूष गोयल, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार

ऊर्जा उत्पादन क्षमता 10 गुनी बढ़ी है। श्री गोयल ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में हमारी प्रतिबद्धता अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के गठन से परिलक्षित होती है। यह पहला संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार के लाखों अवसरों का सृजन हो रहा है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बड़ी संख्या में रोजगार देने वाले मनोरंजन उद्योग में नियामकीय प्रावधान अब स्व-घोषणाओं पर कहीं अधिक निर्भर करेंगे। मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्मों की शूटिंग सुनिश्चित करने के लिए एकल खिड़की मंजूर की सुविधा भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी दी जाएगी, जो केवल विदेशी फिल्म निर्माताओं को ही उपलब्ध है। उन्होंने कहा, 'हम पायरेसी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में एंटी-कैमकॉर्डिंग प्रावधानों को भी शामिल करेंगे।'

श्री गोयल ने कहा, 'हम अगले पांच वर्षों में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं और इसके बाद अगले आठ वर्षों में दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखते हैं।' उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष करों के संग्रह में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और कर आधार भी बढ़ गया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2017-18 में पहली बार 1.06 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किए हैं, जो मुख्यतः विमुद्रीकरण के कारण संभव हुआ है।

श्री गोयल ने कहा कि हम वित्तीय प्रतिभूतियों के लेन-देन पर लगाए और एकत्रित किए गए स्टाम्प शुल्क में सुधार करेंगे। वित्त विधेयक के जरिए इसमें आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है। एक लेन-देन से संबंधित एक लिखित पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से एक ही स्थान पर एकत्रित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार एकत्रित किए गए शुल्क को क्रेता ग्राहक के अधिवास के आधार पर राज्य सरकारों के साथ निर्बाध रूप से साझा किया जाएगा।

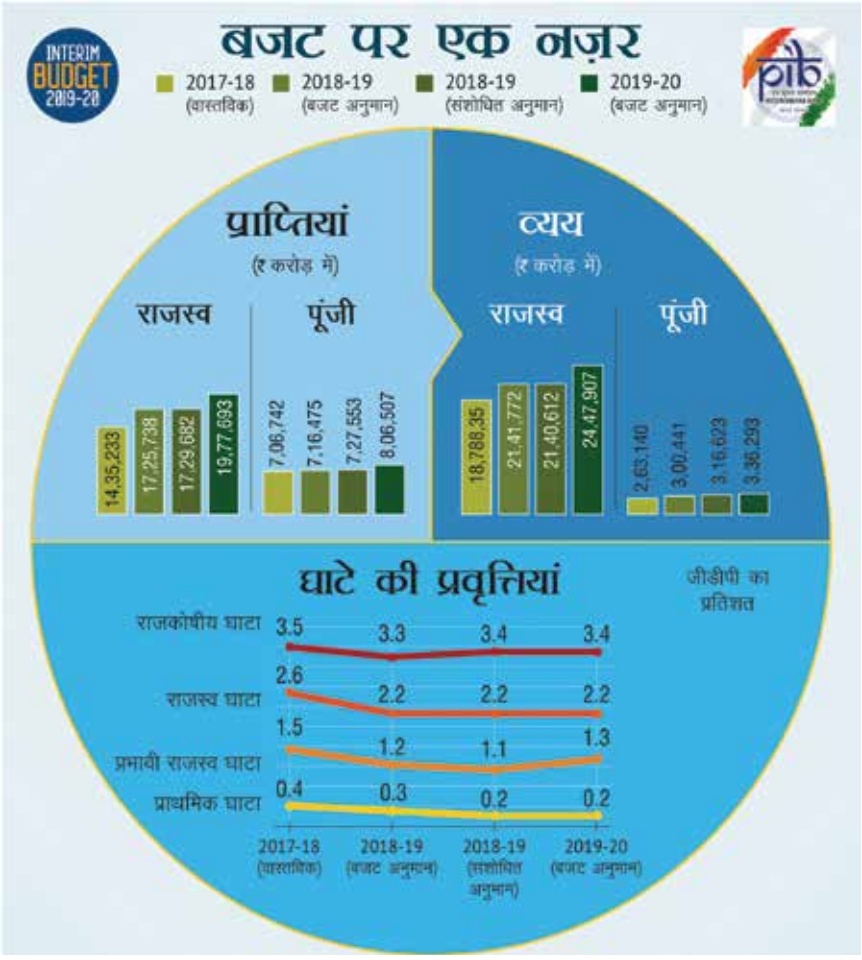

2019–20 के बजट अनुमान में समग्र व्यय 27,84,200 करोड़ रुपये

कुल मिलाकर समग्र व्यय वर्ष 2018-19 के संधोधित अनुमान के 24,57,235 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 27,84,200 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें 3,26,965 करोड़ रुपये अथवा लगभग 13.30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह महंगाई की कम दर को देखते हुए अपेक्षाकृत ज्यादा वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने इस ओर ध्यान दिलाया कि राजकोषीय घाटा समेकन कार्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद सरकार अब ऋण समेकन पर फोकस करेगी। उन्होंने कहा, 'हमने राजकोषीय घाटे के 3 प्रतिशत के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना बरकरार रखा है, जिसे वर्ष 2020-21 तक हासिल किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में भारत का ऋण–जीडीपी अनुपात 46.5 प्रतिशत था। एफआरबीएम अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के ऋण–जीडीपी अनुपात को वर्ष 2024-25 तक घटाकर 40 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा, 'राजकोषीय घाटा समेकन कार्यक्रम के पूरा होने के साथ ही हम अब ऋण समेकन पर फोकस करेंगे।' ■

अंतरिम बजट 2019–20 की मुख्य बातें

मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर राहत

केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए एक फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

नई घोषणाएं

किसान

❖प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसान के बैंक में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएंगी। इससे 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम से 75,000 करोड़ का वार्षिक व्यय होगा।

❖संशोधित अनुमान 2018-19 में अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में 75,000 करोड़ रुपये का व्यय।

❖राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये किया गया।

❖गऊ संसाधनों के अनुवांशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा।

❖1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मत्स्य पालन विभाग।

❖पशुपालन और मछली पालन कार्यों में लगे किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ, इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी।

श्रम

❖प्रधान श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित श्रेत्र के 10 करोड़ कामगारों के लिए निश्चित मासिक पेंशन। केवल 100/55 रुपये का प्रति माह अंशदान देने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन।

स्वास्थ्य

❖22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा।

मनरेगा

❖मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्ताव

❖5 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट।

❖मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर राहत।

❖मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।

❖बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की जा रही है।

❖आयकर की वर्तमान दरें जारी रहेंगी।

❖अपने कब्जे वाले दूसरे घर पर अनुमानित किराये में कर छूट।

❖आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा।

❖किराये पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव।

❖पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान तक बढ़ाया जाएगा।

❖सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि अब आयकर कानून की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई जा रही है।

❖बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराये पर आयकर की छूट एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया।

राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत

❖वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत।

❖राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य 2020-21 तक हासिल किया जाएगा।

❖राजकोषीय घाटे को 2018-19 आरई में घटाकर 3.4 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 7 वर्ष पूर्व करीब 6 प्रतिशत था।

❖वर्ष 2019-20 में कुल व्यय को 13 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ रुपये पर लाया जाएगा।

❖वर्ष 2019-20 के लिए पूंजीगत व्यय 3,36,292 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

❖केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए आवंटन वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3,27,679 करोड़ रुपये होगा।

❖राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2019-20 में आवंटन करीब 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपये किया गया।

❖एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिए आवंटन 18 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपये किया गया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि

❖अनुसूचित जाति के लिए आवंटन में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 76,801 करोड़ रुपये किया गया, जो 2018-19 में 56,619 करोड़ रुपये था।

❖अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत की वृद्धि कर 2019-20 में इसे 50,086 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि 2018-19 में यह 39,135 करोड़ रुपये था।

❖सरकार को विश्वास है कि वह 80 हजार करोड़ को विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर लेगी।

❖राजकोषीय घाटा समेकन कार्यक्रम के साथ ऋण समेकन पर विशेष ध्यान।

गरीब और पिछड़ा वर्ग

❖देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का

❖गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें।

❖शहरों और गांव के बीच की खाई को पाटने और गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित व्यय।

s ❖सभी इच्छित परिवारों को मार्च 2019 तक बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।

पूर्वोत्तर

❖2018-2019 के बजट अनुमानों की तुलना में 2019-20 बजट अनुमानों में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए आवंटन को 58,166 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जायेगा।

❖अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में वायु मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।

❖मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।

❖ब्रह्मपुत्र नदी की उन्नत नौवहन क्षमता के माध्यम से कंटेनर कार्गो का आवागमन।

वंचित वर्ग

❖सभी शेष गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों की पहचान के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नई समिति।

❖गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों के विकास और कल्याण के लिए समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कल्याण विकास बोर्ड।

रक्षा

❖रक्षा बजट पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपये को पार किया।

रेल

❖बजट से 2019-20 (अनुमानों) में 64,587 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव किया गया।

❖समग्र पूंजी व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये किया गया।

❖संचालन अनुपात के वर्ष 2017-18 98.4 प्रतिशत से 2018-19 के 96.2 प्रतिशत और 2019-20 (बजट अनुमानों) में 95 प्रतिशत तक सुधार।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं व्यापारी

❖जीएसटी पंजीकृत एसएमई उद्यमों के लिए एक करोड़ रुपये के वृद्धिशील ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट।

❖सरकारी उपक्रमों में 25 प्रतिशत में से कम से कम 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों के लिए होगा।

❖आंतरिक व्यापार पर अधिक ध्यान देते हुए डीआईपीपी को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग का नाम दिया गया।

डिजिटल ग्राम

❖सरकार अगले पांच वर्षों में 1 लाख ग्रामों को डिजिटल ग्रामों में परिवर्तित करेगी।

अन्य घोषणाएं

❖आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहायता के लिए एक नवीन राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल का गठन। ■

अंतरिम बजट 2019–20 का मुख्य संदेश

सभी को शौचालय, जल और बिजली सुलभ होगी

वर्ष 2022 तक 'नए भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में कदम

- एक ऐसा स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत जिसमें सभी लोगों को शौचालय, जल और बिजली सुलभ होगी
- एक ऐसा भारत जिसके किसानों को आमदनी दोगुनी होगी
- युवाओं और महिलाओं के सपनों को साकार करने हेतु उनके लिए व्यापक अवसर
- एक ऐसा भारत जो आतंकवाद, सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से मुक्त होगा

अगले दशक के लिए विजन

- पिछले पांच वर्षों में भारत की तरक्की और विकास की नींव डाली गई
- अगले पांच वर्षों में पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर
- इसके बाद अगले आठ वर्षों में दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा

वर्ष 2030 के भारत के लिए विजन के आयाम

- भारत एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी से संचालित एवं उच्च विकास दर के साथ एकसमान और पारदर्शी समाज होगा
- इस परिकल्पना के प्रथम आयाम के अंतर्गत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और सहज-सुखद जीवन के लिए भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करना है।

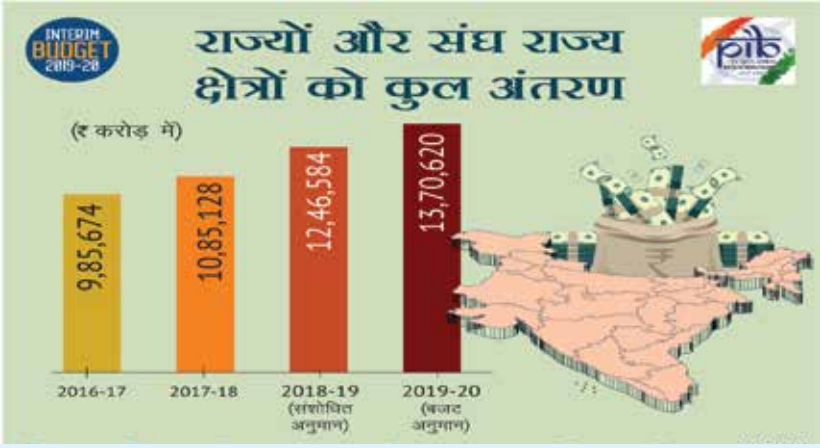

- परिकल्पना के दूसरे आयाम के अंतर्गत एक ऐसे डिजिटल भारत का निर्माण करना है, जहां हमारा युवा वर्ग डिजिटल भारत के सृजन में व्यापक स्तर पर स्टार्ट-अप और इको-सिस्टम में लाखों रोजगारों का सृजन करते हुए इसका नेतृत्व करेगा।
- भारत को प्रदूषण मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान देना।
- आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगिकीकरण के विस्तार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन करना।
- सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित पेयजल के साथ स्वच्छ नदियां और लघु सिंचाई तकनीकों को अपनाने के माध्यम से सिंचाई में जल का कुशल उपयोग करना।
- सागरमाला कार्यक्रम के प्रयासों में तेजी लाने के साथ भारत के तटीय और समुद्री मार्गों के माध्यम से देश के विकास को सशक्त बनाना।
- हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम– गगनयान, भारत दुनिया के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का 'लांच पैड' बन चुका है और 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना इस आयाम को दर्शाता है।
- सर्वाधिक जैविक तरीके से खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न निर्यात में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और विश्व की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का निर्यात करना।
- 2030 तक स्वस्थ भारत और एक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल एवं व्यापक आरोग्य प्रणाली के साथ-साथ आयुष्मान भारत और महिला सहभागिता भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक होगा।
- भारत को न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन वाले एक ऐसे राष्ट्र का रूप देना, जहां एक चुनी हुई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सहकर्मियों और अधिकारियों के शासन को मूर्त रूप दिया जा सकता है। ■

देश के समग्र विकास एवं हर वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित है बजटः अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 1 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीं के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा संसद में पेश किये गए बजट 2019 की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि 'बजट 2019' देश के समग्र विकास एवं हर वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित बजट है।

मीडिया को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के सभी वर्गों किसान, मजदूर एवं मध्यम वर्ग को 'बजट 2019' से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से जो अपेक्षा थी, यह उसे पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि 'बजट 2019' एक सर्वांगीण बजट है। यह विकास को गति प्रदान करने वाला और रोजगार का सृजन करने वाला बजट है। आज के बजट ने यह पुनः प्रमाणित किया है कि मोदी सरकार देश के गरीब, किसान और युवाओं के सपनों एवं आकांक्षाओं को समर्पित सरकार है। इस सर्वस्पर्शी बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों तक जिन वर्गों के बारे में सोचा तक नहीं गया, इस बजट में उन समुदायों के कल्याण का भी ख़याल किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन, मछुआरा समाज के कल्याण के लिए 'मत्स्य पालन' विभाग और सदैव से उपेक्षित घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए "कल्याण बोर्ड" इसी का परिचायक है।

गरीब किसानों के लिए समर्पित बजट

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले गरीब किसानों के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना' एक ऐतिहासिक पहल है, जिसके अंतर्गत देश के करीब 12 करोड़ किसानों को मोदी सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए के बजट से प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जायेंगे। ये रकम दो-दो हजार के तीन किस्तों में सीधे किसानों के एकाउंट में पहुंचेगा। इस योजना के लिए केंद्र सरकार 75 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सहन करेगी। यह देश के किसानों की इनकम को दोगुना करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते हैं, उन किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। बैंक के कर्ज माफ होने से उन्हीं किसानों को फायदा मिलता है जो बैंक से ऋण लेते हैं लेकिन देश में करोड़ो किसान ऐसे हैं जो बैंक से ऋण नहीं लेते हैं, उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलेगा और हर वर्ष मिलेगा। यह फैसला किसानों की आय दो गुना करने के प्रयास में मील का पत्थर साबित होगी, इसके लिए मैं भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक के लिए किसानों को सहायता देने की यह योजना देश के हर गरीब और छोटे किसानों को खेती की शुरुआत

करने में मददगार साबित होगी। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट में दिए जाने ब्याज में 2% कि छूट और समय से ऋण चुकाने पर 3% छूट से किसानों को 5% तक ब्याज में छूट देने का निर्णय किसानों को बड़ी राहत देगा। इस किसान हितैषी निर्णय के लिए मोदी का अभिनंदन। देश के किसान को अब समय पर मदद मिलने से कृषि उत्पादन में भी सुधार होगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। खेती पर होने वाले खर्च को कम करने, किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नए बाजार मुहैया कराने तथा कृषि क्षेत्र में आय के नए साधन जोड़ने के लिए नई सोच के साथ इन पांच वर्षों में काम किया गया है। मोदी सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लेकर किसानों की स्थिति में सुधार लाने का सराहनीय कदम उठाया है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वैज्ञानिक तरीकों से खेती में मदद मिले, इसके लिए देशभर में कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मिट्टी की सेहत के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए 17 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग भी की गई है। फसल खराब होने की स्थिति में

किसानों पर आने वाले संकट में सहायता के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों को फसल बेचने में आसानी हो, इसके लिए देश की 1,500 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का अभियान चलाया गया है। फसलें बाजार तक पहुंचने में खराब न हो, उनका सही भंडारण हो सके, इसके लिए देशभर में जगह-जगह नए कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। फसल के बाद खेतों से निकलने वाले अवशेष से भी किसानों की कमाई हो सके, इसके लिए 'वेस्ट टु वेल्थ' अभियान चलाया जा रहा है।

मध्यम वर्ग के लोगों का कल्याण : मोदी सरकार की प्राथमिकता

मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'बजट 2019' में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाये हैं। पहले केवल ढाई लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट मिलती थी, अब इनकम टैक्स से छूट की सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूर्ण रूप से कर मुक्त करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार द्वारा मध्यम वर्ग के हित में किये जा रहे विभिन्न अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रयासों की कड़ी में यह एक बड़ा निर्णय है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मध्यम वर्ग की सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। डेढ़ लाख रुपये तक निवेश करने वाले लोगों को अब साढ़े छः लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा तो इस तरह से आयकर में छूट की सीमा साढ़े छः लाख रुपये तक हो गई है। इसके अतिरिक्त और कई रियायतें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए की गई हैं। अब मध्यम वर्ग के लोगों को एक अतिरिक्त घर का रेंट बेनिफिट भी मिलेगा। साथ ही, पिछले बजट में लाए गए स्टैंटर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लगातार साढ़े चार साल तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के मध्यम वर्ग के लोगों को विभिन्न तरीकों के माध्यम से लाभ पहुंचाने में कार्यरत रही है। चाहे वह महंगाई नियंत्रण हो, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़े समाज के लिए 10% आरक्षण की बात हो, कम ब्याज दरों पर आवास ऋण की योजना हो, रीयल एस्टेट कानून (रेरा) बिल्डरों की जवाबदेही तय करना हो,एसटी में लगातार रियायत की कवायद हो या इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं के जरिये विकास और रोजगार सृजन की बात हो, हर क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से मोदी सरकार सतत प्रयत्नशील रही है। इस बजट में इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार ने टैक्स-फ्री इनकम को डबल कर दिया, जिससे आयकर की सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़कर पांच लाख रुपये हो गई जो सीमा निवेश करने के आधार पर साढ़े छः लाख रुपये तक पहुंचती है।

श्री शाह ने कहा कि बैंकों एवं डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर कर की कटौती की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। इससे छोटे जमाकर्ताओं और नौकरी न करने वाले दंपत्तियों को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा, किराए के संबंध में कर की कटौती की सीमा को 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि छोटे करदाताओं को राहत दी जा सके।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के मध्यम वर्ग के लोगों को विभिन्न तरीकों के माध्यम से लाभ पहुंचाने में कार्यरत रही है। चाहे वह महंगाई नियंत्रण हो, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़े समाज के लिए 10% आरक्षण की बात हो, कम ब्याज दरों पर आवास ऋण की योजना हो।

गौ–संवर्द्धन एवं गौ–संरक्षण

कामधेनु संवर्द्धन आयोग की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि गौ माता का सनातन संस्कृति व भारतवर्ष से अटूट रिश्ता है। मोदी सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए से इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' एक अभूतपूर्व कदम है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी सरकार का कोटि-कोटि अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में गौ-संवर्द्धन और गौ-संरक्षण, दोनों प्रमुख रूप से उल्लेखित हैं। उन्होंने कहा कि गायों की नस्ल को सुरक्षित करना, उसे बढ़ावा देना और गौ-शालाओं का निर्माण करने जैसे कई कार्यों को पूर्ण करने में कामधेनु संवर्द्धन आयोग सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में भी चाहे पूज्य बापू हों या बिनोवा भावे हों, सबने गाय के महत्व को हमारे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में स्वीकार किया है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कामधेनु संवर्द्धन आयोग के माध्यम से बल देने का सराहनीय प्रयास किया है।

श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की सराहने करते हुए श्री शाह ने कहा

कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की व्यवस्था समाज के गरीब, शोषित एवं वंचित तबके को सशक्त करने का एक सार्थक प्रयास है। प्रधानमंत्री 'श्रम योगी मानधन योजना', दशकों से विकास की मुख्यधारा से वंचित असंगठित क्षेत्र में कार्यरत देश के गरीब श्रमिकों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता की परिचायक है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत भारत सरकार में पेंशनर के जितना ही कंट्रीब्यूट करेगी। यह योजना रिक्शा चलाने वालों, ठेला चलाने वालों जैसे छोटे-छोटे काम करने वाले कामगारों और खुदरा मजदूरी करने वाले सभी श्रमिकों की वृद्धावस्था को पार करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी बोनस और बोनस मिलने की पात्रता, दोनों को बढ़ाकर मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत देने का काम किया है। संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर और कामगारों को 7000 रुपए तक का बोनस और बोनस मिलने के लिए पात्रता को 21,000 प्रति माह बढ़ने के निर्णय से निचले स्तर पर कार्यरत वर्ग को बड़ी राहत देने के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार अपने पहले बजट से ही श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित रही है। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, श्रम मानकों में सुधार, 12 रुपये और 330 रुपये के मामूली प्रीमियम पर जीवन बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा जैसे कई कदम इस दिशा में उठाये गए हैं। अब सरकार ने उन श्रमिक वर्गों के कल्याण के लिए कदम उठाये हैं, जो अभी तक सामाजिक लाभ की इस योजना से वंचित थे।

मछुआरा एवं घुमंतू समुदाय के कल्याण के लिए उठाये गए कदम

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि "सबका साथ, सबका विकास" मोदी सरकार का मूलमंत्र है। मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य है विकास की मुख्यधारा से वंचित समाज के अंतिम लोगों को विकास की प्रथम पंक्ति में लाना। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में अमूल्य योगदान देने वाले मछुवारा समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र सरकार में "मत्स्य पालन" विभाग बनाये जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मछुवारा समुदाय को देने से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करने वाले मछुआरा समुदाय के लिए भी मत्स्य पालन विभाग को अलग से सृजित कर मोदी सरकार ने एक नई शुरुआत की है। अब देश के करोड़ों मछुआरों के कल्याण के लिए यह मत्स्य पालन विभाग सीधे काम करेगा, जिससे मछुआरे भाई-बहनों का कल्याण करने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि घुमंतू समुदाय के लिए भी मोदी सरकार ने अलग से एक आयोग बनाकर घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए नया इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा कि देश में घुमंतू समुदाय सदैव से उपेक्षित व विकास से वंचित रहा है, लेकिन अब नया आयोग बनने से इन घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए अब सीधा काम करने का माध्यम बनेगा। मोदी सरकार द्वारा इस वर्ग के कल्याण के लिए बनाये गए "कल्याण बोर्ड" और उनकी पहचान के लिए नीति आयोग अंतर्गत बनाये गए आयोग से उनके विकास के प्रयासों को स्थायित्व और गति देने के लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं।

ग्रामीण विकास

डिजिटलाइजेशन पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि एक लाख गांवों को डिजिटल करने का जो निर्णय केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लिया गया है, उससे गांवों में रोजगार का सृजन बढ़ेगा, गांवों एवं शहरों का अंतर भी कम होगा। साथ ही, ग्रामीण शिक्षा एवं स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यह गांवों को सेल्फ-सफिशियेंट बनाने में मदद करेगा। इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई देता हूं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत 3 लाख से अधिक जन सुविधा केंद्र करीब 12 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। साथ ही, आज भारत में दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा मिल रहा है। सरकार एक ऐसे डिजिटल भारत के निर्माण के प्रति संकल्पबद्ध है जहां हमारे युवा स्टार्ट-अप और इको-सिस्टम से लाखों लोगों को रोजगार दे सके। साथ ही, सरकार का लक्ष्य आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगीकीकरण को बढ़ाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री शाह ने कहा कि मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। अब तक लगभग 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए गए। इससे सालाना 50 हजार करोड़ रुपए मूल्य की बिजली की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच साल में 1.53 करोड़ घर बनाए गए। यह पहले के मुकाबले पांच गुना है। साथ ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए 2018-19 में एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। 2013-14 में मात्र 92 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मनरेगा के लिए भी 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

रक्षा एवं रेल बजट में अभूतपूर्व वृद्धि

रक्षा बजट में हुई अभूतपूर्व वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद से देश के रक्षा बजट में सबसे बड़ा प्रावधान इस बजट में किया गया है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की देश की रक्षा के प्रति समर्पित प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहले वन रैंक, वन पेंशन और अब रक्षा बजट के लिए रिकॉर्ड राशि का आवंटन, निश्चित रूप

से मोदी सरकार ने इसके माध्यम से सैनिकों के परिवार को सम्मान और देश की सुरक्षा सुनिशिचित की है। वर्षो से उपेक्षित देश की सुरक्षा सदैव मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। मोदी सरकार ने अपने हर निर्णय से हमारे सैनिकों का मनोबल और देश का मान बढ़ाया है। आज मोदी द्वारा रक्षा बजट को अब तक का सर्वाधिक 3 लाख करोड़ रुपए करने पर उनका ह्रदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आवश्यकता पड़ने पर रक्षा बजट में और वृद्धि की जायेगी।

इसी तरह रेलवे के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा 1.58 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले बजट में यह रकम 1.48 लाख करोड़ थी। पिछला साल रेलवे से लिए सबसे सुरक्षित रहा। ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्वस्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए।

मोदी सरकार नॉर्थ–ईस्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध

बजट में देश के नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के विकास के लिए उठाये गए क़दमों की प्रशंसा करते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए पहले दिन से कटिबद्ध है। मोदी सरकार ने अपने पहले दिन से ही उत्तरपूर्व के विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि रोड, रेल एवं एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों को देश के बाकी राज्यों से जोड़ा गया है। अब मोदी सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के लिए आवंटित निधि में 21% की अभूतपूर्व वृद्धि कर इन राज्यों में विकास को नया आयाम देने का प्रयास किया है। इस बजट में उत्तर पूर्व के विकास के बजट को 21% बढ़ाकर 58 हजार करोड़ करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। इस निर्णय से उत्तर पूर्व भी देश के विकास की मुख्यधारा से तेजी के साथ जुड़ेगा। यह उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए आज तक की सबसे बड़ी बजटीय वृद्धि है। नॉर्थ-ईस्ट के विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार के कमिटमेंट को यह पुनः प्रतिष्ठित करता है।

इससे पहले मोदी सरकार ने 'डोनर' मंत्रालय को नए सिरे से गति दी। हर महीने कोई न कोई केन्द्रीय मंत्री उत्तर-पूर्व के राज्यों में प्रवास करते हैं और सरकार की योजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग करते हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं मातृ वंदना योजना

महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के योगदान पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। मोदी ने महिलाओं के विकास को महिलाओं के नेतृत्व में विकास में परिभाषित करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और माताओं को धुएं के अभिशाप से मुक्त करने वाली उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को 8 करोड़ करना इसी का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता को देखते हुए अब इसे और वृहद् स्वरूप में लागू करने की योजना बनाई गई है। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किये। अब केंद्र सरकार ने 2 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन और देने का निर्णय लिया है। यह निश्चित रूप से देश की गरीब महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के अनेक प्रयास किये हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% लोन महिलाओं को मिले जिससे उनके जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन हुआ। साथ ही, इस बजट में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1,330 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इतने सारे सुधारवादी कदम उठाने के बावजूद राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने में मोदी सरकार सफल रही है। उन्होंने कहा कि यह बजट वित्तीय समझदारी और जन-कल्याण के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए भी राजकोषीय घाटे को महज 3.4% पर सीमित किया गया है, जो यूपीए सरकार के समय 6% तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के सभी फोर कॉर्नर्स को मेंटेन करते हुए देश के विकास की गति तेज हुई है। इसके कारण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को पांच साल तक महंगाई की दर को कंट्रोल रखने में जो सफलता मिली है, यह अगले साल भी इसी तरह नियंत्रित रहेगी।

श्री शाह ने कहा कि यह लघु उद्योगों को तेज गति देने वाला बजट है, क्योंकि उन्हें बैंक लोन में भी 2% ब्याज की छूट दी गई है। पहले छोटे उद्यमियों एवं व्यापारियों के लिए 40 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय को जीएसटी से छूट के बाद अब ब्याज में भी 2% की छूट देकर मोदी सरकार ने लघु उद्योगों एवं छोटे उद्यमियों के कल्याण के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। इससे देश में रोजगार के और अवसर सृजित होंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के 70 सालों में गरीब-कल्याण के लिए जितने कार्य नहीं हुए, वे सभी कार्य केवल पांच वर्षों प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर दिखाए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किये गए, लगभग 8 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया, ढाई करोड़ घर बनाए गए, लगभग 19 हजार घरों में बिजली पहुंचाई गई, दो करोड़ से अधिक घरों को रौशन किया गया है।

श्री शाह ने कहा कि 2030 तक स्वस्थ भारत के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए अहर्निश प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि 2030 तक स्वस्थ भारत और एक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ आयुष्मान भारत और महिला सहभागिता भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। देश के गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों अर्थात लगभग 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, जिससे काफी कम समय में ही लगभग 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।

इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,572 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसमें से 2100 करोड़ रुपये सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए दिए गए हैं।

अन्तरिक्ष कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम-गगनयान, भारत दुनिया के उपग्रहों को छोड़ने का लांच पैड बन चुका है और 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना हमारा लक्ष्य है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार का स्पष्ट मानना है कि देश के संसाधनों पर पहला हक़ गरीबों का है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास को जन आंदोलन बनाया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस लोक-कल्याणकारी बजट के माध्यम से देश के विकास को एक नई ऊर्जा और गति दी है। आज हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं। साथ ही, आज भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो जल्द ही पांचवें स्थान पर पहुंच जायेगी। विकास की इस रफ़्तार को हम अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रखेंगे, इस विश्वास के साथ मैं फिर से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल को पार्टी एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस लोक-कल्याणकारी बजट के माध्यम से देश के विकास को एक नई ऊर्जा और गति दी है। आज हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं। साथ ही, आज भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो जल्द ही पांचवें स्थान पर पहुंच जायेगी।

भ्रष्टाचार नियंत्रण

श्री शाह ने कहा कि रेरा कानून और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अब बच नहीं सकते। बैंकों का तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज रिकवर हो चुका है। 2.6 लाख करोड़ रुपए का रि-कैपिटलाइजेशन किया गया है।

केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार का विजन 2030

- सामाजिक और वास्तविक ढांचे को नेक्स्ट जेनरेशन का बनाने के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ईज ऑफ लिविंग की दिशा में काम करेगी।
- डिजिटल इंडिया बनाने और हर नागरिक तक इसे पहुंचाने में हमारे युवा अहम रोल निभाएंगे। उनके लिए स्टार्टअप और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।
- क्लीन और ग्रीन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ाने, रिन्युएबल एनर्जी का मुख्य स्रोत बनने, आयात पर निर्भरता कम करने और लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
- आधुनिक औद्योगिक तकनीकों के जरिए ग्रामीण इलाकों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों, स्टार्टअप को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा।
- नदियों को साफ बनाया जाएगा ताकि सभी नागरिकों को पीने का साफ पानी, स्वस्थ और लंबा जीवन मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
- लंबे समुद्र तट हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं। इसके लिए ब्लू इकोनॉमी और सागरमाला के तहत काम किया जा रहा है। समुद्र और समुद्र तट हमारे विजन 2030 का छठा आयाम हैं।
- 2022 तक भारत विश्व के लिए लॉन्च पैड बन जाएगा। इस साल तक हम अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजेंगे।
- कृषि और खाद्य उपज बढ़ाने में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। ऑर्गेनिक फूड पर फोकस।
- 2030 विजन में स्वस्थ भारत नौवां आयाम है। इसके तहत संकट रहित और व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर देंगे।
- मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत सक्रिय, जिम्मेदार, दोस्ताना नौकरशाही को बढ़ावा देना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पर फोकस। ■

अंतरिम बजट (2019) और पांच साल की दिशा

अरुण जेटली

श्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के उन उच्च नीतिगत फैसलों को आगे बढ़ाता है, जो उन्होंने इस राष्ट्र के समक्ष रखे है। हालांकि, चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अंतरिम बजट वोटों को लुभाने वाले होते रहे है और इसका असर अगली सरकार बनने तक ही होता है। लेकिन हमने यह साबित किया है कि निर्णायक रूप से देश की प्रगति के लिए अर्थव्यवस्था में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है और उन्हें लिया जा सकता है। हमारे पास साल 2009 और 2014 के तात्कालिक उदाहरण हैं जहां अंतरिम बजट में टैक्स दरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे।

अंतरिम बजट किसी भी सरकार के लिए एक मौका होता है जिसके माध्यम से वह अपने पांच वर्षों के प्रदर्शन का लेखा-जोखा जनता के समक्ष रखती है। इसके माध्यम से सरकारें भविष्य की नीतियों पर अपने दृष्टिकोण को भी रेखांकित करती है। ऐसे ही श्री पीयूष गोयल के बजट भाषण को देखा जाना चाहिए।

मैं यहां पिछले पांच वर्षों के प्रदर्शन और अंतरिम बजट में भविष्य की दिशा का विस्तार और वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं।

राजनीतिक रूझान

बजटीय प्रावधानों, कर नीति और प्रशासनिक कदमों के माध्यम से पिछले पांच वर्षों का राजनीतिक रूझान एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ओर रहा है जो निर्णायक फैसले लेने में सक्षम और भ्रष्टाचार से मुक्त है। पिछलें पांच वर्षो के आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ठोस स्वरूप दिया है, इसकी क्षमता को उजागर किया है और हमें एक आर्थिक शक्ति के तौर पर विश्व में स्थापित किया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है और एक ऐसा राष्ट्र के रूप में सामने आ रहे है, जहां व्यापार करना आसान हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने भारत को एक निर्णायक सरकार प्रदान की है जो कठिन निर्णय लेने में भी सक्षम है।

सुधार

पिछले पांच सालों में विकास की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया गया, और उच्च विकास दर हासिल कर इसका प्रयोग देश की गरीब जनता, ग्रामीण इलाकों, कृषि क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया गया। वहीं इस दौरान करदाताओं को भी बड़ी राहत प्रदान की गई। सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों को अपनाते हुए पारदर्शी तरीके से काम किया, जिसमें सरकारी कामकाज में अनुज्ञा और अनुमोदन को समाप्त करना, और अनुबंध, लाइसेंस और प्राकृतिक संसाधनों के मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय लेना शामिल है। ऐसे ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान कर जनता को पूर्ण लाभ पहुंचाने और राज्यों के सशक्त करने का काम भी किया गया।

सरकार के प्रमुख सुधारों में जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की प्रक्रिया में मानवीय भागीदारी को सीमित किया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों की दरों में कमी के कारण करदाताओं की संख्या में विस्तार स्पष्ट नजर आता है। सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए बड़ा निवेश किया है, जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण दबाव के दौर से गुजर रहा था। हमारी सरकार ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू करने के साथ ही प्रमुख ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, कम लागत वाले बीमा, पेंशन योजना और एमएसएमई के वित्तपोषण के लिए जरूरी कदम उठाए, जिससें सभी प्रमुख बैंकिंग सेक्टरों में सुधार हुआ है। विमुद्रीकरण उच्च-नकदी वाली अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा हमला था। नकदी का चलन हमारे तंत्र में काले धन, कर चोरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे रहा था, जिस पर विमुद्रीकरण के बाद काफी हद तक लगाम लगाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। वहीं विमुद्रीकरण ने हमारी अर्थव्यवस्था को औपचारिकता प्रदान करने का भी काम किया। विमुद्रीकरण के बाद कर संग्रह में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और वहीं अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। रिजर्व बैंक के संदर्भ में भी जरुरी कदम उठाए गए, जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। आधार द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट पहचान संख्या एक महत्वपूर्ण सुधार है जो केवल भारत के कुछ लोगों के लिए ही अजीब है। इसमें भारत की 99% आबादी शामिल किया जा चुका है।

सामाजिक क्षेत्र में सुधार जैसे कि वित्तीय समावेशन, हर परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, हर घर को बिजली, हर घर को रसोई गैस, हर घर में एक शौचालय को पिछले पांच वर्षों में देखा गया है।

हमारी नीतियों की बदौलत भारत एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और नागरिक उड्डयन, बिजली, स्मार्ट शहरों, मेट्रो

सिस्टम, बेहतर शहरी सुविधाओं में सुधार स्पष्ट देखा जा सकता है।

7वें केंद्रीय वेतन आयोग, ओआरओपी के कार्यान्वयन और न्यू पेंशन स्कीम में किए गए सुधारों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और अर्ध-सैन्य बलों को लाभ हुआ है।

आर्थिक आंकड़े

भारत की आर्थिक स्थिरता में निर्विवाद रूप से साल 2014 से 2019 का समय इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला समय कहा जा सकता है। इन पांच साल की अवधि के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 7.5% रहने का अनुमान है। वही मुद्रास्फीति 4% के भीतर रखने में हम कामयाब रहे। पिछले पांच वर्षों में राजकोषीय घाटा यूपीए-2 सरकार के 5.3% से गिरकर 3.7% हो गया है। हम चाहते है कि पांच सालों के बाद यह आकंड़ा 3.4% हो। हालांकि हम 3.3% का लक्ष्य लेकर चले थे, लेकिन मौजूदा बजट की घोषणाओं को देखते हुए राजकोषीय घाटा 3.4% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपीए-2 के पांच वर्ष के दौरान चालू खाते का घाटा 3.3% से 5.6% रहा, जो अब गिरकर 1.5% के औसत स्तर पर आ गया है। इसी तरह, जीडीपी के लिए बाहरी ऋण मार्च, 2018 तक 23.9% से नीचे आकर 20.5% हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 396 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, वहीं इन पांच सालों में यह आकंड़ा 425 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर को भी छू चुका है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में निवेश के लिहाज से एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है।

भारतीय मध्यम वर्ग

श्री पीयूष गोयल ने बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें 5 लाख तक की आय वालें नागरिकों को टैक्स दायरें से बाहर रखा गया है। यह घोषणा मध्यम वर्ग को प्रभावी रूप से मजबूत करती है जिसकी क्रय शक्ति का विस्तार भारत के भविष्य की कुंजी है।

7वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल कार्यान्वयन, लंबे समय से लंबित ओआरओपी का निपटारा, नई पेंशन योजना में सुधार, उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करोड़ों का ऋण, मध्यम आय वर्ग के लिए आवास सब्सिडी का प्रावधान, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में राहत और यूपीए द्वारा दोहरे अंकों में छोड़ी गई मुद्रास्फीति को 2% पर सीमित रखा, मध्यम वर्ग के लिए यह सभी कदम राहत लेकर आते है।

हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया है। इस दौरान टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से 2.5 लाख किया गया। इसके बाद, स्लैब में बदलाव किए बिना, 3 लाख तक की आय वाले नागरिकों टैक्स छूट के दायरे में लाया गया। ऐसे ही 3 से 5 लाख तक की आय वाले लोगों के लिए कर दर को घटाते हुए 10% से 5% किया गया और आज इस श्रेणी को पूरी तरह छूट दी गई है। यदि इसमें आयकर अधिनियम के तहत अन्य कर राहतें को इसमें जोड़ दिया जाता है, तो इन लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि ही होती है। आवास ऋण पर ब्याज दर को 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख किया गया। ऐसे ही धारा 80 C के तहत मिलने वाली छूट को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया।

सरकार का मानना है कि वेतनभोगी कर्मचारी चाहे वह सरकारी तंत्र से जुड़ा हो या फिर निजी क्षेत्र से टैक्स देने वाला एक ईमानदार समूह हैं। उनके पूरे कर को स्रोत पर ही काट लिया जाता है। इसलिए पिछले साल सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को राहत देते हुए रु 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की बात कही थी और इस साल यह लाभ रु 50,000 तक बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल, कर भुगतान और बीमा पर मिलने वाले लाभों की सीमा भी अधिक है। इस प्रकार अगर भारत के नियो-मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को दिए गए इन सभी लाभों को जोड़ दिया जाए, तो लगभग 8 लाख कमाने वाले नागरिक पर वर्तमान समय में न के बराबर टैक्स देनदारी हैं।

जैसे-जैसे कर आधार बढ़ता है, वैसे—वैसे सरकार की क्षमताओं में भी वृद्धि होती है।

जीएसटी को 19 महीने पहले लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद टैक्स दरों में भारी कमी देखी गई है, इन टैक्सों की उच्चतम दर जो 31% थी, आज 18%, 12% और 5% दायरे में सिमट कर रह गई है। इतिहास में किसी भी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान टैक्स दरों में कमी और मध्यम वर्ग को राहत की बात, दोनों एक साथ कम ही देखने को मिलता है। टैक्स दरों में कम के साथ ही इसका आधार बढ़ा है और वहीं टैक्स संग्रह का आकंड़ा भी उत्साहजनक है, जो हमारी सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि मानी जा सकती है। यह संभव हुआ है क्योंकि हमने एक भ्रष्टाचार विरोधी सरकार चलाने का साहस दिखाया और गैर कानूनी तरीकों से होने वाले कामों को और अधिक कठिन बना दिया है।

यूपीए सरकार के दौरान दोहरे अंकों में पहुंची मुद्रास्फीति को हमने 4% के आस-पास सीमित रखा, जिसके कारण ब्याज दरों में कमी आई है, जिससे मकान एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण लेने वालों को राहत मिली है।

हाल के एक वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि भारत के मध्यम वर्ग का दायरा साल 2005 में 18% था, जो साल 2015 में बढ़कर 29% हो गया और साल 2025 तक यह आंकड़ा 44% को छू सकता हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए हमारी यह दिशा न केवल जारी रहे, बल्कि इस वर्ग को भविष्य में और अधिक समृद्धि बनाया जाए।

आधारभूत ढांचा

आधारभूत ढांचा जाति, पंथ या धर्म को मान्यता नहीं देती है। यह एक ऐसी सुविधा है जो राज्य सभी को प्रदान करता है। हम आज दुनिया के सबसे तेज राजमार्ग निर्माण

वाले देश माने जा रहे हैं। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हमारे बंदरगाह अपनी क्षमता का विस्तार कर रहे है और लाभ कमा रहे है। नागरिक उड्डयन के मोर्चे पर, हम पहले से ही 100 कार्यात्मक हवाई अड्डों के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती नागरिक उड्डयन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। हमारे राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। भारतीय रेलवे न केवल प्रत्येक दिन अपना विस्तार कर रहा है, बल्कि अपनी सेवाओं और गुणवत्ता में भी सुधार कर रहा है। ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार जारी है, जिससे हर घर बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। गैर-पारंपरिक ऊर्जा पर भी हमारा जोर, जो अब परिणाम देने लगा है। पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक बजट ने बुनियादी ढांचे पर व्यय का विस्तार किया है। अंतरिम बजट भी उसी दिशा को बनाए रखने में कामयाब हुआ है।

गरीब

हमारी सरकार को गांधी जी के उस मंत्र द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी का चेहरा याद करें जिसे आपने देखा होगा, और अपने आप से पूछें, क्या आपके द्वारा उठाया गया कदम उसके काम का है या नहीं? क्या वह इसके द्वारा कुछ हासिल करेगा?

सरकार ने उपरोक्त मंत्र को महत्व देते हुए, पहले ही दिन से इस दिशा में काम किया। भारत के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। विशिष्ट पहचान ने यह सुनिश्चित किया कि सरकारी सहायता सीधे गरीबों तक पहुंचे और इसके दुरुपयोग से बचा जा सके। इसमें खर्च होने वाले पैसे का लाभ गरीबों को मिले। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सभी इस समावेशी कार्यक्रम का विस्तार है। शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं ने यह सुनिश्चित किया है कि 2022 तक भारत के हर परिवार के सिर पर छत हो। भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से को सस्ते राशन के लिए सबसे बड़ा आवंटन करके भोजन का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। मनरेगा पर वास्तविक खर्च को दोगुना करने से यह सुनिश्चित हो रहा है कि ग्रामीण बेरोजगारी को सीमित कर, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों को आजीविका का स्रोत मिल सके। थोड़े समय में जीवन के अधिकार को सम्मानजनक बनाने के लिए, सरकार ने सुनिश्चित किया कि भारी संख्या में ग्रामीण घरों को शौचालय का निर्माण हो। बीपीएल परिवार रसोई गैस अपना रहे हैं। हर इच्छुक घर को बिजली से जोड़ा गया है।

शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में गैर-आरक्षित वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण प्रदान करने का फैसला लिया गया है। आयुष्मान भारत को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। इसके तहत भारत की 40% आबादी को 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। अंत्योदय कार्यक्रम के तहत भारत के 115 कम विकसित जिलों की पहचान कर उनका विकास किया जा रहा है।

पिछले पांच वर्षों में भारत के श्रमिक वर्ग के लिए बोनस, ग्रेच्युटी और कई अन्य लाभों में उदारीकरण की नीति को देखा गया है। उसी दिशा में श्रमिकों के लिए मासिक रु 3000 की पेंशन सुनिश्चित करने वाली प्रमुख योजना भी है। प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को रु 3,000 मासिक पेशन का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए कर्मचारी और सरकार एक समान योगदान देंगे। प्रभावी रूप से, यह सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और भारत को अधिक पेंशनभोगी समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में गैर-आरक्षित वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण प्रदान करने का फैसला लिया गया है। आयुष्मान भारत को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। इसके तहत भारत की 40% आबादी को 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। अंत्योदय कार्यक्रम के तहत भारत के 115 कम विकसित जिलों की पहचान कर उनका विकास किया जा रहा है।

परंपरागत रूप से, इस देश के गरीबों को आकर्षक नारे दिए गए, जिनका प्रभाव अल्पकालिक था और जिसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं था। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता गैरी बेकर ने बताया कि गरीबी का कारण यह नहीं है कि गरीब अमीरों से कम सक्षम होते हैं, बल्कि गरीब इसलिए गरीब होता है क्योंकि उनका ज्यादातर वक्त रोज़मर्रा की तंगी से निपटने में ही चला जाता है, उसके सामने केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने की मजबूर होती है।

भारत के गरीबों को केवल नारों का लाभ मिला, लेकिन आज उनके पास संसाधनों पहुंच रहे है, जिसके चलते यह वर्ग भारत के नियो मध्यम वर्ग में शामिल होने का प्रमुख दावेदार बन गया है।

कृषि

पिछले साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी और हर किसान अपनी इनपुट लागत से 50% अधिक पाने का हकदार होगा। प्रो. स्वामीनाथन ने स्वयं सरकार के फैसले की सराहना की है। दूसरों ने केवल इसका वादा किया था, हमारी सरकार ने इसे करके दिखाया। हालांकि, कुछ राज्यों में खरीद प्रणाली की अपर्याप्तता को देखते हुए कई किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिला और उन्हें अपनी उपज को कम कीमतों पर बेचना पड़ा। सरकार ने ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं। हमनें कृषि ऋण को बढ़ाया है, फसल बीमा योजना को सुनिश्चित किया है, सिंचाई में निवेश बढ़ाया है और यह

हमारी अर्थव्यवस्था की मांग है कि भारतीय किसान जो हमें अधिशेष उत्पादन देता है वह और अधिक समृद्धि बने। किसान कल्याण जैसे कार्यक्रम और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने बजट में छोटे और सीमांत किसानों को रु 6000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। यह हमारे खाद्य उत्पादकों के आर्थिक सशिक्तकरण के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। इसके चलते वित्त वर्ष 2018-19 में सरकारी खर्चों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और राजकोषीय घाटे के हमारे अनुमानों को भी यह निर्णय प्रभावित करेगा, लेकिन हम एफआरबीएम समिति की सिफारिशों के अनुसार शानदार पथ पर बने रहने के लिए आश्वस्त हैं। भारतीय किसान की क्रय शक्ति बढ़ने वाले इस प्रावधान पर होने वाले खर्च की तुलना में भविष्य में इसके शानदार असर हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा।

भविष्य का लक्ष्य

भविष्य में भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। अगले दशक के मध्य तक हम इसे हासिल कर लेंगे और उसके बाद अर्थव्यवस्था के उस आकार को दोगुना करने का लक्ष्य रखेंगे। वर्तमान विकास दर के साथ हम इसे प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारी इस प्रतिबद्धता का लाभ हर भारतीय हो और यह विकास केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त राजवंशों तक ही सीमित न रह जाए। हम एक ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जहां गरीबी दूर हो, भारत के पूर्वी क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों के साथ बढ़े, ग्रामीण भारत में शहरी जैसी सुविधाएं हों, और औपचारिक क्षेत्र में महिला के लिए रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े। खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन की क्षमता को बढ़ाने, वैश्विक गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, भारत को इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में अग्रणी बनाने, वस्त्र और परिधान का एक प्रमुख केंद्र बनाने जैसे मुद्दों पर काम किया जा रहा है, जिससे भविष्य की चुनौतियां का सामना किया जा सके हैं। जैविक खेती एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ ही शहरों के आधुनिकीकरण और नवीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

हम अन्य तुलनीय अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व है। फिर भी हम अधीर हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की अपनी वर्तमान स्थिति से भी तेजी से बढ़ना चाहते हैं, ताकि हम छूटे हुए ऐतिहासिक अवसरों को भी प्राप्त कर सकें।

हम एक ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जहां गरीबी दूर हो, भारत के पूर्वी क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों के साथ बढ़े, ग्रामीण भारत में शहरी जैसी सुविधाएं हों, और औपचारिक क्षेत्र में महिला के लिए रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े। खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन की क्षमता को बढ़ाने, वैश्विक गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, भारत को इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में अग्रणी बनाने, वस्त्र और परिधान का एक प्रमुख केंद्र बनाने जैसे मुद्दों पर काम किया जा रहा है।

अंत में एक प्रतिक्रिया

हाल ही में कुछ लोगों द्वारा विशेष तौर पर दो मुद्दों पर टिप्पणियां की गई हैं। पहला अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन से संबंधित है और दूसरा जीडीपी पर विमुद्रीकरण के प्रभाव पर।

पिछले पांच वर्षों में औसतन 7.5% जीडीपी वृद्धि देखी गई है। यदि मुद्रास्फीति का आंकड़ा इसमें जोड़ा जाता है, तो वृद्धि दर औसतन 11.5 से 12% के बीच होगी। क्या यह कल्पना करना संभव है कि नियंत्रित मुद्रास्फीति के बावजूद इतनी उच्च वृद्धि दर के बाद भी देश में किसी प्रकार का कोई रोजगार सृजन नहीं हुआ होगी। इपीएफओ और अन्य आंकड़े रोजगार सृजन की ओर एक विस्तृत संकेत देते है। यदि कोई रोजगार सृजन नहीं हुआ है, जैसाकि कथित है, तो देश में तार्किक रूप से एक महान सामाजिक अशांति होनी चाहिए थी, लेकिन विगत पांच वर्ष एक भी बड़े विरोध प्रदर्शन के बिना ही बीत गए।

जीडीपी विकास पर विमुद्रीकरण के तात्कालिक प्रभाव पर विश्व स्तर पर कोई मापदंड़ स्थापित नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री का यह कथन कि 'इससे जीडीपी में 2% की गिरावट आएगी' ने सरकार के आलोचकों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। साल 2016-17 और 2017-18 के लिए न तो मूल डेटा और न ही पहले संशोधन ने यह साबित किया। जब भारत में एक बड़ी समानांतर अर्थव्यवस्था थी, तो हम सभी को बताया गया था कि हमारे विकास के आंकड़े जीडीपी के विकास आंकड़ों को पूर्णतः परिभाषित नहीं करते हैं, क्योंकि औपचारिक अर्थव्यवस्था के बाहर बहुत सारी गतिविधि होती है। जब विमुद्रीकरण के फैसले ने पूरी नकदी को बैंकिंग प्रणाली में जमा करने का साहस दिखाया और भविष्य के लेनदेन का लेखा-जोखा रखने योग्य बनाया, तो तार्किक रूप से जीडीपी को पोस्ट-डिमोनेटाइजेशन बढ़ाना ही था। वहीं विमुद्रीकरण का प्रभाव केवल क्षणिक हो सकता है ऐसा सरकार हमेशा कहती रही है। वर्तमान आंकड़े इसे निर्णायक रूप से स्थापित करते है। साल 2016-17 और 2017-18 के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में उच्च कर संग्रह ही इस आंकड़े को अब और आगे बढ़ाएगे। अर्थव्यवस्था का विस्तार तब तक संभव नहीं है, जब तक कर संग्रह का दायरा न बढ़ाया जा सके। विकास के आंकड़े अनुमान पर आधारित नहीं होते हैं, कर संग्रह ही वास्तविक आंकड़े को परिभाषित करता है। ■

(लेखक केंद्रीय मंत्री हैं)

'ओडिशा में जनजातियों की स्थिति बद से भी बदतर'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 फरवरी को भगवान् महाप्रभु की नगरी पुरी (ओडिशा) में विशाल आदिवासी समावेश को संबोधित किया और आदिवासी एवं अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रतिबद्धता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य की बीजद सरकार की विफलता का उल्लेख करते हुए 2019 में देश में फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया।

श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार के समय जनजातीय बजट के लिए केवल 30,700 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जबकि मोदी सरकार ने इस बजट में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए 50,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जहां जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए महज 4,000 करोड़ रुपये दिए थे, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार ने इसमें 50% की वृद्धि करते हुए लगभग 6,275 करोड़ रुपये की राशि दी है। उन्होंने कहा कि सोनिया-मनमोहन सरकार के 10 वर्षों की यूपीए सरकार में आदिवासी भाई-बंधुओं के कल्याण के लिए केवल 166 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए गए, वहीं मोदी सरकार ने पांच वर्ष में ही 288 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा चुके हैं। यदि केवल ओडिशा की बात की जाय तो पांच वर्ष पहले ओडिशा में जहां केवल 6 एकलव्य मॉडल स्कूल थे, वहीं मोदी सरकार के पांच वर्षों में यह संख्या बढ़कर 103 हो गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी भाइयों को पहले जहां केवल छः वन उपज पर समर्थन मूल्य मिलता था, वहीं मोदी सरकार ने 49 वन उपज पर समर्थन मूल्य देने का फैसला किया है जो करोड़ों आदिवासी भाई-बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में आदिवासी छात्रों के लिए जहां यूपीए की सरकार में केवल 144 करोड़ रुपये मिलते थे, वहीं पिछले पांच सालों में मोदी सरकार ने इसके लिए 329 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किये हैं। उन्होंने कहा कि लगभग साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये की राशि से आदिवासी छात्रों के लिए 500 नए हॉस्टल का निर्माण विगत पांच वर्षों में हुआ है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के आदिवासियों के लिये सबसे बड़ा काम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाने का किया है। उन्होंने कहा कि खदानों की पारदर्शी नीलामी से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा लगभग 9,000 करोड़ रुपये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के लिए निर्धारित किये गए हैं।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी भगवान् बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर भव्य स्मारक बनाने का का कार्य कर देश की आन-बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान देशभक्त योद्धाओं को सम्मान देने का महती कार्य किया है। इसके साथ ही, महारानी दुर्गावती, वीर भीमानायक सहित कई नाम, अनाम आदिवासी विभूतियों का स्मारक बनाकर मोदी सरकार ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में अनुसूचित जनजाति के महानायकों के बलिदान को आज से पहले किसी कांग्रेसी सरकार ने याद नहीं किया। यह मोदी सरकार है जिसने उनके योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्हें उचित सम्मान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने मानगढ़ में ट्राइबल स्वातंत्र्य सेनानियों के म्यूजियम को भी बनाने का काम किया है।

दाना मांझी के साथ हुई अमानवीय घटना का जिक्र करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ओडिशा में जनजातियों की स्थिति बद से भी बदतर है। दाना मांझी का उदाहरण देश की जनता ने देखा है। शर्म आनी चाहिए ओडिशा के मुख्यमंत्री को जो एक मां के शव को उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी न कर पाए। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री इतना भी नहीं कर सकते, उन्हें राज्य की सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भी ओडिशा में 42% लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। ■

'राज्य की भ्रष्टाचारी एवं अराजक तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकें'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 29 जनवरी को पूर्वी मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) जिले के कांथि रेलवे स्टेशन रोड मैदान, पद्मपुकरिया (कोंट्टई) में एक विशाल जन-सभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से राज्य की भ्रष्टाचारी एवं अराजक तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया।

अमर शहीद खुदीराम बोस की जन्मभूमि और बंकिम चन्द्र चटर्जी की कर्मभूमि को नमन करते हुए श्री शाह ने कहा कि 2019 का लोक सभा चुनाव 'सोनार बांग्ला' के निर्माण का चुनाव है। सोनार बांग्ला की संकल्पना को साकार करने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं होती, वहां विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे 'सोनार बांग्ला' का निर्माण करना चाहती है जो रवींद्र संगीत और चैतन्य महाप्रभु के भक्ति गीतों से गुंजायमान हो, जो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बताये रास्ते पर आगे बढ़ता हो। इसके लिए पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को मजबूत करना आवश्यक है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये पर बड़ा हमला करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि क्या पश्चिम बंगाल में हमें प्रचार करने का हक़ है या नहीं? हम रथ लेकर पश्चिम बंगाल के गांव-गांव जाना चाहते थे, घर-घर जाना चाहते थे, जन-जन तक जाना चाहते थे, लेकिन ममता दीदी ने हमें राज्य की जनता से मिलने नहीं दिया जबकि यह हमारा लोकतांत्रिक एवं जनतांत्रिक अधिकार है। ममता दीदी, आप चाहे जितने अवरोध पैदा कीजिये, हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के जन-जन तक कमल का संदेश लेकर जायेंगे।

श्री शाह ने कहा कि जब यहां के एडीएम ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की रैली के लिए बसें नहीं रोकीं तो आधी रात को तृणमूल सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। ममता दीदी, आप एडीएम पर गुस्सा क्यों होती हैं, जितना गुस्सा करना है, हम पर कीजिये। आपको जितना ट्रांसफर करना है, कर लीजिये,राज्य के जनता पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करके ही रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 65 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई है। हमारे कार्यकर्ताओं का गुनाह क्या था? गुनाह बस इतना था कि वे ममता दीदी के सिंडिकेट का विरोध कर रहे थे, ममता दीदी के परिवारवाद, अराजकता और तृणमूल सरकार संरक्षित लोगों द्वारा बम धमाकों का विरोध कर रहे थे। ममता दीदी, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी को यात्रा के लिए परमिशन न दें, चाहे हमें यात्रा न करने दें, मेरा हेलिकॉप्टर तक न उतरने दें, लेकिन आप राज्य की जनता के दिलों से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को कैसे निकाल पायेंगी। पश्चिम बंगाल की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकास यात्रा से जुड़ने का फैसला कर चुकी है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के वक्त देश की जीडीपी में पश्चिम बंगाल का योगदान देश के अग्रणी राज्यों में से था, लेकिन आज ममता दीदी के शासन काल में राज्य का हर पांचवां व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर है। आज जीडीपी के मामले में 29 राज्यों की

सूची में से पश्चिम बंगाल का स्थान 27वां है। पश्चिम बंगाल में बिजली की औसत खपत राष्ट्रीय खपत से लगभग 30% कम है, क्योंकि राज्य में उद्योग-धंधे बचे ही नहीं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता से राज्य की 55 हजार बंद फैक्ट्रियों को शुरू कर रोजगार देने का वादा किया था। ममता दीदी बताएं कि इनमें से कितनी फैक्ट्रियां शुरू हुई? फैक्ट्रियां तो शुरू हुई नहीं, हां, उसकी जगह हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्री जरूर शुरू हो गई। क्या इस तरह पश्चिम बंगाल का विकास हो सकता है? यह तय है कि ममता दीदी के शासन में पश्चिम बंगाल का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को सरकार चलाने का मौक़ा दिया, लेकिन किसी ने भी पश्चिम बंगाल का विकास नहीं किया। आप एक मौक़ा भारतीय जनता पार्टी को दीजिये, हम पश्चिम बंगाल की गौरवशाली संस्कृति को पुनर्स्थापित करेंगे।

श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार ने गरीबी लाने का पाप किया, कम्युनिस्ट सत्ता में आई तो हिंसा का दौर शुरू हुआ और जब ममता दीदी सरकार में आई तो गरीबी और हिंसा के साथ-साथ सिंडिकेट की अराजकता भी पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई। चिटफंड वाले ममता दीदी की पेंटिंग्स को करोड़ों में खरीदते हैं। जब पेंटिंग वाले ही मुख्यमंत्री हो तो चिटफंड वाली कभी पकड़े भी जा सकते हैं क्या? पश्चिम बंगाल में गरीबों की कमाई चिटफंड घोटाला करने वाले लोग खा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता एक बार राज्य में परिवर्तन लाये, राज्य में भाजपा की सरकार बनाए, हम गरीबों का पैसा हड़पने वाले एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे और उनसे गरीबों की पाई-पाई वापस लाकर रहेंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की तृणमूल सरकार में घुसपैठियों का स्वागत है, लेकिन अपना धर्म बचाने, अपनी बहू-बेटियों की इज्जत बचाने आये शरणार्थियों पर अत्याचार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इसाई शरणार्थियों को आश्वस्त करती है कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिये उन्हें भारत की नागरिकता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरहद से गौ-तस्करी का सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा, घुसपैठ बंद नहीं हो रहे क्योंकि घुसपैठिये तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक हैं। उनके सत्ता में रहते अवैध घुसपैठ रोके नहीं जा सकते। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर घुसपैठिये क्या, परिंदे भी राज्य की सीमा में पर नहीं मार सकते। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ मुक्त पश्चिम बंगाल केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है।

श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। हम पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान जाकर करेंगें? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे आन-बान और शान के साथ सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा संपन्न हो।

केंद्र सरकार की कई योजनाओं का उदाहरण देते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी कई जनोपयोगी योजनायें पश्चिम बंगाल में भेजते हैं लेकिन ममता दीदी उन योजनाओं के नाम बदलकर उस पर तृणमूल कांग्रेस का ठप्पा लगा देती है। ममता दीदी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिये, राज्य की जनता को मालूम है कि ये योजनायें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों में गरीब-कल्याण के लिए जितने कार्य नहीं हुए, वे सभी कार्य केवल पांच वर्षों प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर दिखाए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किये गए, लगभग 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया, ढाई करोड़ घर बनाए गए, लगभग 19 हजार घरों में बिजली पहुंचाई गई, अब घरों को रौशन किया जा रहा है। किसानों को उनकी फसल पर डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया गया। देश के गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है लेकिन ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं करने का निर्णय लिया है क्योंकि उन्हें डर है कि यदि ये योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार का पश्चिम बंगाल से खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों को पश्चिम बंगाल में हर काम के लिए रिश्वत देना पड़ता है, यदि ये स्थिति बदलनी है तो राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी।

गांधी परिवार पर तीखा हमला करते हुए श्री शाह ने कहा कि यूपीए की दस सालों की सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाली 2G सरकार में 12 लाख करोड़ रुपये के घपले-घोटाले हुए थे। अब कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की नई योजना बनाई है। प्रियंका वाड्रा के रूप में तीसरा 'जी' भी आ गया है। पता नहीं, अब यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो कितने लाख करोड़ का घोटाला होगा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो परिवारवाद है ही, तृणमूल कांग्रेस भी इसी रास्ते पर चल रही है। जिस तरह कांग्रेस में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का कब्जा है, ठीक उसी तरह तृणमूल कांग्रेस में भी ममता दीदी के बाद उनका भतीजा तैयार बैठा है। परिवारवाद में यकीन करने वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते।

विपक्ष पर करारा हमला करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तथाकथित महागठबंधन 'मजबूर' सरकार चाहता है जबकि देश की जनता 'मजबूत' सरकार चाहती है और 'मजबूत' सरकार भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अलावा कोई और नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसे देश का नेतृत्व करने वाला 'लीडर' चलाये, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि दलाली करने वाले 'डीलर' चलायें। पश्चिम बंगाल की जनता तय करे कि मोदी के नेतृत्व में 'लीडर' वाली सरकार चाहिए या फिर ममता दीदी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली 'डीलर' वाली सरकार। ■

'उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने अमन कायम किया है'

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 फरवरी को अलीगढ़ में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और राज्य की प्रगति को जारी रखने और देश के हित में जनता के कल्याण व विकास के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को फिर से भारी बहुमत से जिताने की अपील की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 73 नहीं, बल्कि 74 सीटें जीतेगी।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में सत्ता का रास्ता लखनऊ होकर जाता है और इस बार भी चुनाव में यही होगा तथा भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुआ-भतीजा को ही नहीं, बल्कि राहुल बाबा को भी बुला लो, परिणाम वही होगा यानी भारतीय जनता पार्टी 73 नहीं 74 सीटें जीतेगी।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा की और मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ के काम की सराहना की। श्री शाह ने कहा कि उनके शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ और दंगाई राज्य छोड़कर भाग गए। अपराधी डरे हुए हैं, गुंडे पुलिस से डरकर भाग गए हैं और राज्य में अमन चैन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जातिवाद और परिवारवाद से त्रस्त उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शांति स्थापित किया है।

विकास कार्यों की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि मुख्य मंत्री योगी जी ने यहां 24 घंटे बिजली देने का काम किया। डेढ़ साल में हर दिन कम से कम 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य में 144 करोड़ रुपए मूल्य की 140 हेक्टेयर जमीन भू-माफिया से मुक्त करा दी। श्री शाह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि राज्य में भू-माफिया को उलटा लटका दिया जाएगा और यह संभव हुआ। श्री शाह ने राज्य में ऐंटी रोमियो स्क्वाड की सराहना की। राज्य से पलायन रुका है और उसका चहुंमुखी विकास हो रहा है।

2019 के बजट के लिए प्रधान मंत्री की भूरि-भूरि सराहना करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रमुख ने कहा कि यह हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि आज तक देश का सबसे बड़ा रक्षा बजट हमारी सरकार लेकर आई है। उन्होंने कहा प्रधान मंत्री के सत्ता में आने के बाद आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए और धमाके बंद हो गए हैं। उन्होंने सेना के जवानों के शौर्य की चर्चा करते हुए कहा कि उड़ी में हमारे कैंप पर हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जवाबी कार्रवाई का हुक्म दिया और फिर क्या था, अदम्य साहस के धनी हमारे वीर जवानों ने ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया कि दुश्मनों के छक्के छूट गए। जब जवान अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके लौट आए तो बड़ा परिवर्तन आया। उस समय तक दुनिया में सिर्फ दो ही देश थे, जिन्होंने ऐसा कारनामा किया था लेकिन भारत ने यह कार्रवाई करके तीसरा स्थान पाने का गौरव पा लिया। ■

सही शब्द : सही अर्थ-2
प्रकृति, धर्म और संस्कृति

दीनदयाल उपाध्याय

'संस्कृति', व्यष्टि और समष्टि दोनों से संबंध रखती है, यद्यपि संस्कृति का भाव मूलतः समष्टिगत होता है। संस्कृति के माध्यम से जीवन के वैशिष्ट्य अर्थात् समाज की आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। यह सत्य है कि जिस प्रकार ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि के बाद भी दस अंगुल बचा रहता है, उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों से मिलकर बना होने के बाद भी समाज का अपना अलग अस्तित्व और वैशिष्ट्य होता है। इसके साथ ही यह भी उतना ही सत्य है कि जब समाज क्रियाशील होना चाहता है तो उसे अपनी भावनाओं के प्रकटीकरण के लिए व्यक्तियों के पुरुषार्थ का ही सहारा लेना पड़ता है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। किंतु आत्मा शरीर के द्वारा ही कोई काम कर सकती है, उसके बिना नहीं। उसी प्रकार समाज भी व्यक्तियों के बिना काम नहीं कर सकता। अतः संस्कृति मूलतः समष्टिगत होते हुए भी उसका संबंध व्यक्ति से आए बिना रहता नहीं।

व्यक्ति और समाज

अब प्रश्न खड़ा होता है कि व्यक्ति और समाज का परस्पर संबंध क्या? हमें दिखाई देता है कि व्यक्ति एक ही समय में दो प्रकार का अस्तित्व लेकर चलता है। एक ओर तो उसका पूर्णतया पृथक् अस्तित्व है, दूसरी ओर वह समाज के अभिन्न घटक के रूप में भी जाना जाता है। व्यक्ति एक ही समय में दोनों नाते से काम करता है। वह व्यक्ति के नाते भी जीवन प्रकट करता है और समाज के नाते भी। इसलिए दोनों के बीच में योग्य संबंध स्थापित करना बहुत आवश्यक बात हो गई है। दुनिया के समस्त समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों एवं दार्शनिकों के समक्ष यह उपस्थित है। इस बारे में भिन्न-भिन्न मत बने हैं। कहीं तो व्यक्ति को सर्वोपरि माना है और शेष समाज को उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का साधन मात्र माना गया है। अतः उनके यहां व्यक्ति स्वातंत्र्य को ही समस्त सामाजिक गठन का केंद्रबिंदु माना है। यह विचार पश्चिम का है। दूसरी ओर व्यक्ति का समाज से भिन्न कोई अस्तित्व माना ही नहीं। उनका मत है कि समाज ठीक रहा तो व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाता है। व्यक्ति को अपने बारे में बिल्कुल न सोचते हुए केवल समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही खटपट करते रहना चाहिए। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में उन्होंने उसी प्रकार विचार किया, जैसे किसी मशीन के पुर्जे के बारे में किया जाता है। जिस प्रकार कपड़े के थान का एक नमूना देखने से उसी प्रकार के सैकड़ों थान प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी प्रकार एक व्यक्ति को नमूना मानकर उसी नमूने के आधार पर ही सब व्यक्तियों का सामूहिक विचार किया जाता है। उनकी दृष्टि में समूह ही प्रमुख चीज है, व्यक्ति का स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं होता।

ये दोनों विचारधाराएं आज पश्चिम में चल रही हैं। एक के अनुसार व्यक्ति नगण्य, समाज ही सब कुछ है। दूसरे के अनुसार एक व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। अब यदि दो व्यक्तियों की स्वतंत्रता में संघर्ष खड़ा हो जाए तब क्या हो? इसके उत्तर में कहा जाता है कि यह तो जीवन का स्थायी संघर्ष है, इसका कोई उपाय नहीं। इस संघर्ष में वही टिकेगा, जिसके पास अधिक शक्ति होगी। प्रकृति का नियम है कि जो योग्यतम है, वह जीवित रहेगा, शेष लोग समाप्त होते चले जाएंगे।

भारतीय कल्पना

किंतु हमारी संस्कृति के अनुसार व्यक्ति और समाज का अभिन्न संबंध होते हुए भी उन दोनों की सत्ता अलग-अलग है। इसलिए हमने दोनों का विचार किया। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की रक्षा के साथ-साथ समाज की सत्ता का भी ध्यान रखने को बताया। कब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करता है और कब उसे समाज के उपकरण (Instrument) के नाते काम करना पड़ता है-इन दोनों स्थितियों में मेल बैठाने की आवश्यकता है। इसलिए उपनिषदों में कहा है, जो इनमें से एक ही बात का विचार करते हैं, वे ग़लत रास्ते पर चलते हैं। जो लोग केवल व्यक्ति का विचार करते हैं, वे अंधकार को प्राप्त होते हैं तो जो केवल समाज का विचार करते हैं, वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। अतः हमें दोनों का ही विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करके, उसके व्यक्तित्व का संरक्षण करके, उसे विकास का पूरा अवसर दें हम व्यक्ति को मृत्यु से बचाएं, मृत्यु को जीतें और दूसरी ओर समाज का विचार करके हम समष्टि के आधार पर अमरता को प्राप्त करें। एक से मृत्यु को जीतना और दूसरे से अमरता को प्राप्त करना अर्थात् इन दोनों चीजों का एक साथ मेल बैठाने की दृष्टि से हम लोग विचार करें। उदाहरणस्वरूप रोटी को लें। रोटी जीवन के लिए आवश्यक है, पर उसका यह अर्थ तो नहीं कि रोटी खानेवाले लोग मरते नहीं। पर यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर कि रोटी खानेवाले सब लोग एक न एक दिन मर जाते हैं, अतः रोटी नहीं खाऊंगा, उपवास रखना प्रारंभ कर दे तो उसका अंत क्या होगा? निष्कर्ष यह कि न रोटी खाने से अमरता प्राप्त होती है तो जीवित रहने के लिए रोटी खाना आवश्यक है, पर अमर होने के लिए शरीर से सद्कर्म करना आवश्यक होता है। खाना

व्यक्ति के शरीर को क़ायम रखने के लिए आवश्यक होता है, किंतु व्यक्ति को अमर होने के लिए समष्टि का सहारा लेना पड़ता है।

प्रकृति और विकृति

इन दोनों का मेल बैठाना आवश्यक है। दोनों का मेल बैठाना ही संस्कृति का मुख्य कार्य है। व्यक्ति को जो प्राप्त होता है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में भिन्नता रहती है और प्रकृति के नाते यह भिन्नता व्यक्ति-व्यक्ति में प्रवेश करती है। प्रकृति की ओर से प्राप्त होनेवाली सब चीजें-हमारा मन, शरीर, इंद्रियां आदि प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। प्रकृति का अपना धर्म है। मनुष्य बहुत से कर्म प्रकृति-धर्म के वशीभूत होकर ही करता है। संपूर्ण जगत् में व्याप्त प्रकृति स्वयं भी अपना काम नियम से कर रही है। चाहे स्वयं प्रेरणा से, चाहे ईश्वर की योजना से किंतु उसका प्रत्येक कार्य नियमपूर्वक होता है। उसी प्रकार मनुष्य तथा शेष जीव-जंतु भी प्रकृति का काम स्वाभाविक रूप से नियमपूर्वक करते जाते हैं। उदाहरणार्थ, स्वासोच्छ्वास प्राकृतिक कर्म है। उसके लिए हमें कोई विचार नहीं करना पड़ता। सांस अपने आप चलती है। साधारणतया मनुष्य प्रकृति के अनुसार कार्य करता है किंतु यदि कभी वह अपनी बुद्धि के अभिमान में, साधारण प्रकृति के पालन में अविचार, अतिरेक अथवा उपेक्षा कर जाता है तो वह अस्वस्थ हो जाता है। उदाहरणार्थ, बढ़िया चीज़ को भी अधिक खा लेने से पाचन शक्ति ख़राब हो जाती है। अतः इस अतिरेक से बचाना चाहिए। इसको ही हम 'विकृति' कहते हैं। प्रकृति में जब किसी प्रकार का अतिरेक किया जाता है तो वहां पर विकृति आ जाती है। इस विकृति को रोकना नितांत आवश्यक बात है। विकृति को रोकना प्रकृति को ठीक-ठाक चलाए रखने का काम 'धर्म' करता है।

धर्म

धर्म विकृति को रोकता है। इसलिए संस्कृति जिस पहली सीढ़ी से चढ़ती है, वह है धर्म की सीढ़ी। हमारे यहां कहा गया है, "धर्म से ही प्रारंभ है तथा धर्म से धारण है। किसी भी समाज एवं कार्य की धारणा, उसका अस्तित्व धर्म के कारण ही बना रहता है। विकृति के कारण ही सब बुराइयां तथा रोग आते हैं। अपने यहाँ कहा गया है, "जब आदमी मिथ्या आहार-विहार करता है तो उसको रोग लग जाते हैं। यदि हमारा आहार-विहार ठीक रहे, हम प्रकृति के नियमों का ठीक प्रकार से पालन करते जाएं तो रोग होने का कोई कारण ही नहीं। फिर मनुष्य अपनी पूरी आयु प्राप्त करता है। अतः यह बात हमारे यहां धर्म के रूप में समझाई गई है। मनुष्य अपनी प्रकृति के समस्त नियमों का पालन करता रहे, एक-दूसरे के साथ ठीक प्रकार की व्यवस्था रखे, यहां पर वास्तव में धर्म आता है।"

समष्टिगत 'धर्म'

अब इस धर्म का दूसरा पहलू भी प्रकृति के ही अंतर्गत आता है। प्रकृति के अनुसार जीवन की धारणा करने के लिए कार्य करते समय अनुभव आता है कि अनेक कार्य ऐसे हैं, जिन्हें मनुष्य अकेला नहीं कर सकता। कई लोगों के साथ मिलकर ही वह कार्य हो पाता है। उदाहरणार्थ, एक मनुष्य जो कुछ उत्पादन करता है, अपना पूरा समय उसी में लगा देता है। पर अपने अकेले के उत्पादन से ही तो जीवन की सब आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो जातीं। किसी ने अन्न पैदा किया तो किसी ने कपड़ा। दोनों आपस में बांटकर ही अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकते हैं। समाज में परस्पर सहयोग के, दान-प्रतिदान के, आदान-प्रदान के ऐसे अवसर पग-पग पर उपस्थित होते हैं। वास्तव में हमारा संपूर्ण जीवन ही इस लेन-देन के सहारे चलता है। इस लेन-देन एवं पारस्परिक सहयोग की व्यवस्था को ही समाज की व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार दस लोग अपने-अपने व्यक्तियों की रक्षा करते हुए साथ मिलकर चल सकें, ठीक प्रकार से काम कर सकें, उनमें कोई टकराव न हो, इसके लिए कुछ-न-कुछ नियम बनाने ही पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे सड़क पर मोटरों की टक्कर बचाने के लिए सड़क का नियम (Rule of the Road) बनाया गया है। ये सारे नियम और व्यवस्थाएं व्यक्ति की अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। व्यक्ति को अपने प्राकृतिक हितों के संपादन के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों प्रकार के प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है। अतः समाज जीवन में कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित करनी ही पड़ती हैं। ये समस्त व्यवस्थाएं धर्म के अंदर आती हैं। इसमें कहीं भी संस्कृति नहीं आती। यहां तक सब काम धर्म के आधार पर होता जाता है।

संस्कृति और धर्म

किंतु जब हम अपनी व्यक्तिगत प्रकृति का विचार न करके समष्टि का ही विचार करते हैं, व्यक्ति की प्रकृति को समष्टि-प्रकृति अर्थात् समाज का विरोधी न बनाते हुए चलाना चाहते हैं, तब वास्तव में संस्कृति आती है। यह धर्म से एक पग आगे आती है। यह दूसरी सीढ़ी है। इसकी एक ही चिंता रहती है कि व्यक्ति की प्रकृति को समाज विरोधी न बनाते हुए उसे सामूहिक कर्तव्यों द्वारा कैसे स्वस्थ रखा जाए। अतः जहां व्यक्ति निज प्रकृति की कोई चिंता न करके केवल समष्टिगत एवं परार्थ भाव से कार्य करने को प्रवृत्त होता है, वहीं संस्कृति प्रारंभ होती है। संस्कृति के मोटे-मोटे लक्षण देखना ही हो तो हम कोई भी कार्य करते समय विचार करें, यह कार्य निजी स्वार्थ से प्रेरित तो नहीं? अगर उसके मूल में स्वार्थ नहीं है। वह संस्कृति के अनुसार कार्य हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि हम स्वार्थ को पूर्णतया बुरा मान लें। प्रकृति की रक्षा के लिए कुछ अंशों तक स्वार्थ बहुत ही आवश्यक है। वास्तव में स्वार्थी शब्द वहीं ख़राब होता है, जहां अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्यों के स्वार्थ को हानि पहुंचाई जाती है। यदि किसी के स्वार्थ को हानि न पहुंचाते हुए अपना स्वार्थ पूर्ण किया जाए तो वह बुरा नहीं। क्योंकि यह साधारण प्रवृत्ति है। किंतु जब हम संस्कृति का विचार करते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे कार्य शुद्ध परार्थ भाव से हों। तभी हम कह सकेंगे कि हम अपने कार्य की प्रेरणा संस्कृति से पाते हैं। ■

-पाञ्चजन्य, जुलाई 13, 1959

पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस नहीं रहे

(3 जून 1930 –29 जनवरी 2019)

प्रख्यात समाजवादी एवं पूर्व रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस का 29 जनवरी 2019 को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के मैक्स अस्पताल में 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली।

श्री जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म मैंगलोर (कर्नाटक) में हुआ था। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। 1967 के संसदीय चुनाव में बॉम्बे साउथ सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री एसके पाटिल को हराकर वे देशभर में मशहूर हुए। आपातकाल के विरोध में संघर्ष किया। बाद में बिहार के मुजफ्फरपुर से 1977 में वह सांसद बने और उन्हें उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। जनता पार्टी सरकार में उन्होंने स्वदेशी के मुद्दों को आगे बढ़ाया। इसके बाद वे जनता दल के साथ हो गए। वह वीपी सिंह सरकार के कार्यकाल में रेल मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने 1989 और 90 में कोंकण रेलवे का विस्तार कराया और मेंगलुरु को मुंबई से जोड़ा। 1994 में उन्होंने अपनी नई पार्टी समता पार्टी बनाई। बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक का भी दायित्व संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वह दो बार रक्षा मंत्री रहे। यह दौर इसलिए महत्वपूर्ण था कि उस दौरान पोकरण में भारत में परमाणु बम का परीक्षण किया और 1999 में करगिल का युद्ध लड़ा। ■

शोक संदेश

जॉर्ज साहब ने भारत की बेहतरीन लीडरशिप का प्रतिनिधित्व किया। वह बेबाक और निर्भीक थे। उन्होंने देश के लिए अमूल्य योगदान दिया। वह गरीबों की सबसे मजबूत आवाज थे। उनके निधन से दुःखी हूं।'

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की ओर से जारी शोक–संदेश

देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेता श्री जॉर्ज फर्नांडीज के निधन के समाचार से अत्यंत दुखी हूं। उनके राजनीतिक व्यक्तित्व और नेतृत्व ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर दशकों तक अमिट छाप छोड़ी है। वे एक उत्कृष्ट राजनेता और समर्पित समाजसेवी थे।

बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री जॉर्ज फर्नांडीज का भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक योगदान रहा है। वे समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे। वे ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के भी प्रमुख रहे। वे 1967 में पहली बार लोक सभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वे नौ बार लोकसभा के सांसद रहे। अपने संसदीय जीवन में वे संसद की कई कमिटियों का हिस्सा रहे और उन्होंने रक्षा एवं रेलवे सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। लोकतंत्र के सजग

प्रहरी श्री फर्नांडीज आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता की प्रखर आवाज बनकर उभरे, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1977 में उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा और बिहार के मुजफ्फरपुर से भारी बहुमत से जीत हासिल की। आपातकाल के दौरान उनके संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने NDA के संयोजक के रूप में भी अहम भूमिका निभाई।

कई भाषाओं के जानकार श्री फर्नांडीज का पूरा जीवन समाज की उन्नति और राष्ट्र के विकास के प्रति समर्पित रहा। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य रहा है। अपने सौम्य व्यक्तित्व और जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाने वाले एक उत्कृष्ट समाजसेवी, सांसद एवं जुझारू जन-नेता के रूप में वे सदैव याद किये जायेंगे। उनका निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है।

दुःख की इस घड़ी में मैं स्वयं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी, 2019 को केंद्र सरकार ने महान समाजसेवी स्वर्गीय श्री नानाजी देशमुख (मरणोपरांत), देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. प्रणब मुखर्जी और महान गायक और प्रसिद्ध संगीतकार श्री भूपेन हजारिका (मरणोपरांत) को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित करने की घोषणा की।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि 'भारत रत्न' का सम्मान नानाजी देशमुख को एक विनम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि नानाजी ने अपना पूरा जीवन गरीब से गरीब लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे एकात्म मानववाद के दर्शन में दृढ़ विश्वास रखते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण स्वालंबन के क्षेत्र में उनका अद्वितीय योगदान जो देश के करोड़ों लोगों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान की भी स्थापना की थी। वे सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र मनीषी थे जिनके चिंतन में हमेशा समाज और राष्ट्र का विकास सबसे ऊपर था।

भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। वे एक ऐसे उत्कृष्ट राजनेता हैं जिनका एक लंबे समय तक कानून निर्माता के रूप में सार्वजनिक जीवन देश और राष्ट्र की सेवा के प्रति उनका निस्वार्थ समर्पण देश व समाज के लिए प्रेरणादायक है। देश में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो परस्पर संवाद और सार्वजनिक संभाषण के प्रणेता हैं। डॉ. मुखर्जी उनमें से एक हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भूपेन हजारिका जी, जिन्हें सुधाकंठ के नाम से जाना जाता है, ने भारतीय संगीत और फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका संगीत मानव संवेदना से ओत-प्रोत था और उनकी कला मानवता और सार्वभौमिक भाईचारे के लिए एक अदम्य प्रेरणास्रोत थी। उन्होंने भारत की संगीत परंपरा को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। भूपेन जी का यह सम्मान देश के उत्तर-पूर्व के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पूरा भारत उनकी अद्भुत संगीत कला से मंत्रमुग्ध होता रहता है। उनके लिए भारत रत्न की संस्तुति करने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभारी हूं। ■

प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी श्री नानाजी देशमुख एवं प्रख्यात संगीतकार श्री भूपेन हजारिका को 'भारत रत्न' से सम्मानित किए जाने के निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नानाजी देशमुख द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान हेतु की प्रशंसा की और कहा, "नानाजी देशमुख के ग्रामीण विकास में जो योगदान दिया उससे हमारे गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक नई राह दिखाई। उन्होंने दलितों के प्रति विनम्रता, करुणा और सेवा का हमेशा भाव दिया है। वे सही मायने में भारत रत्न हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा, "भूपेन हजारिका के गीत और संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों द्वारा सराहे जाते रहे हैं। इससे न्याय, सौहार्द और भाईचारे का संदेश जाता है। उन्होंने विश्व स्तर पर भारत की संगीत परंपराओं को लोकप्रिय बनाया। मुझे प्रसन्नता है कि भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।" श्री प्रणब मुखर्जी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, "प्रणब दा हमारे समय के एक उत्कृष्ट राजनेता हैं। उन्होंने दशकों तक देश की निस्वार्थ और अथक सेवा की है, जिससे उन्होंने देश के विकास की राह पर एक मजबूत छाप छोड़ी है। उनके ज्ञान और बुद्धिमता के समान कोई दूसरा नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।"

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में 70वां गणतंत्र दिवस परेड में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री माटेमाला सिरिल रामाफोसा, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और अन्य

नई दिल्ली में राजघाट पर शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सूरत (गुजरात) में न्यू इंडिया यूथ कॉनक्लेव को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मदुरई (तमिलनाडु) में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते तमिलनाडु भाजपा नेतागण

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
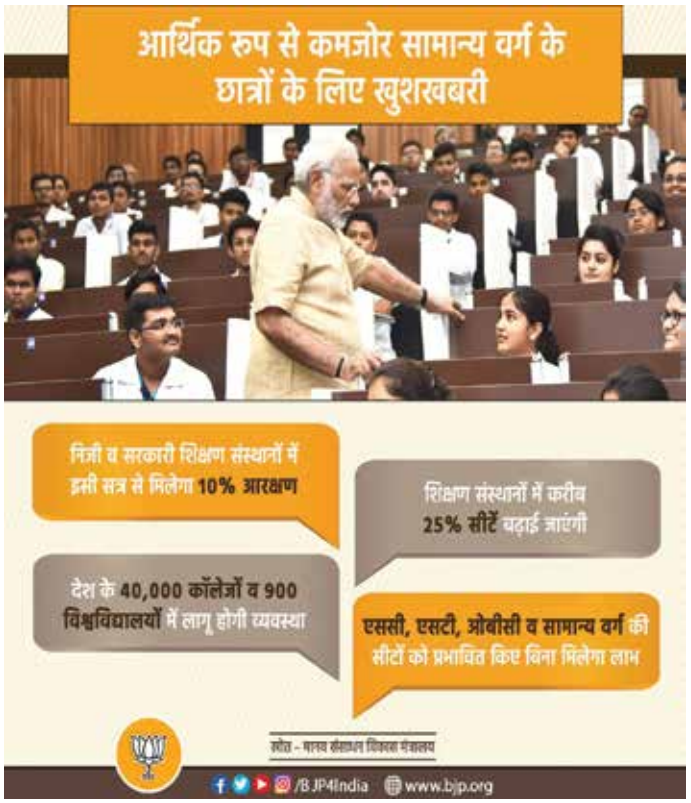
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-19